स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–19, अंक–8, श्रावण–भाद्रपद 2068, अगस्त 2011

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्रा, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा-4

बढ़ती महंगाई से बौखलाई सरकार इसे रोकने के लिए कोई भी कारगर कदम नहीं उठा पा रही है. . . लेकिन पिछले एक साल से यह सभी हदें पार करते हुए आम लोगों का जीवन दूभर बना रही है।

अनुक्रम

आवरण लेख
महंगाई पर सरकार का शुतुरमुर्गी रवैया
– डा. अश्विनी महाजन /4

मंदी
कर्ज के भँवर में अमरीका
– निरंकार सिंह /7

दृष्टिकोण
ताकवर है अपना शेयर बाजार
– आलोक पुराणिक /10

असमानता
असमानता पर उदासनीता
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /12

सामयिकी
खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश
– उमेश चतुर्वेदी /14

अर्थ–तंत्र
क्या हो विकास की सही परिभाषा
– भारत डोगरा /17

पर्यावरण
पर्यावरण के मोर्चे पर शिकस्त
– जगमोहन /20

मुद्दा : देश विरोधी आचरण
– बलवीर पुंज /22

समस्या
सीआईए और मोसाद एजेंसियों के खतरनाक खेल
– ब्रजमोहन जैन /24

आतंकवाद : आतंकियों को अभयदान क्यों?
– अरुण जेटली /26

अंतर्राष्ट्रीय : आतंकवाद से त्रस्त चीन
– वेदप्रताप वैदिक /29

लेख : भारतीय नारी पर पश्चिमी प्रभाव
– रेणु पुराणिक /31

विचार–विमर्श : प्रतिभाएं बनाएंगी आर्थिक महाशक्ति
– जयंतीलाल भंडारी /32

पाठकनामा/2, रपट/34 आंदोलन/35

पाठकनामा

नेता ही भ्रष्ट तो कौन सुने जनता की पुकार

स्वदेशी पत्रिका का हर अंक मैं अपने दोस्त के यहां पढ़ता हूँ। जहां तक मैं जानता हूँ कि प्रत्येक सरकार का फर्ज बनता है कि वो अपने नागरिकों का ध्यान रखें। परंतु आजादी के 64 साल बीत जाने के बाद भी आज आम आदमी को कुछ नहीं मिला। अगर मिला है तो केवल गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। पिछले 6 सालों से महंगाई इस तरह बढ़ रही है कि वह गरीब आदमी की जान लेने को तुली हुई है।

आज प्रत्येक देशवासी घोटालों से चिंतित है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेलों में इतने घोटाले हुए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी इस घोटालों में लिप्त पाई गयी। लेकिन क्या कहने कांग्रेस सरकार के जिन्होंने मुख्यमंत्री को माफ कर दिया। यह वही सरकार है जो कहती है कि हर आदमी को काम और हर आदमी को रोटी।

अगर देखा जाए तो आज हर पार्टी में नेता केवल अपना भला चाहते है। उन्हें आम आदमी से कोई सरोकार नहीं। उन्हें तो बस पैसा चाहिए – पैसा। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के साथ जो कुछ हुआ वो देश की जनता से छिपा नहीं है। एक साधु और दूसरा समाजसेवी जिन्होंने भ्रष्टाचार को मिटने के लिए अपना आंदोलन जारी रखा है लेकिन केन्द्र सरकार है कि उन्हें दिन–प्रति–दिन किसी न किसी मुद्दे में फंसती रहती है। क्या हो गया है आज नेताओं को और क्या हो गया है आज के नागरिकों को, जो बात तो भ्रष्टाचार को मिटाने की करते है लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आगे नहीं बढ़ते। मैं स्वदेशी पत्रिका के माध्यम से लोगों को आह्वान करता हूँ कि आज प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य के साथ–साथ धर्म भी बनता है कि वो भ्रष्टाचार को अपने देश से सदैव के लिए मिटे दें।

– महेन्दर मिस्त्री (ठेकेदार) गली नं. 3, सत्य विहार, बुराड़ी, नई दिल्ली

जनता करे कारवाई

आज चीनी ड्रैगन का खूनी पंजा हमारी सरहद पर कब्जा कर रहा है। चीन सामान हमारे बाजार में अपनी पैठ बना चुका है। हर जगह चीनी सामान का बोल–बोला है। इलैक्टॉनिक्स से लेकर हार्डवेयर तक इसने अपनी पैठ बना ली है। तो दूसरी और पाक की आतंकी हरकत दिनोंदिन कश्मीर समस्या को बढ़ावा दे रही हैं वहीं दूसरी ओर नक्सलियों ने समूचा छत्तीसगढ़, बिहार अपने कब्जे में ले रखा है। हमारे नेता हैं कि उन्हें भ्रष्टाचार करने से ही फुर्सत नहीं मिलती तो वो इन मुद्दों पर क्यों ध्यान देंगे। अब समय आ गया है कि जनता को अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। उसे भी लीबिया और यमन जैसी कारवाई करने चाहिए ताकि इन भ्रष्ट नेताओं को गद्दी से उतार कर फैंक देना चाहिए।

– राकेश कुमार दास, मीडिया अपार्टमेंट, इंदिरापुरम्, गाजियाबाद

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com
अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

सरकार गोदामों से अनाज मुक्त करे तो खुले बाजार में कीमतें जरूर गिरेंगी। सरकार घाटे की वजह से ऐसा नहीं कर रही है। क्या लोग भूखे मरें और सरकार नुकसान की चिंता करती रहे?

– यशवंत सिन्हा

सरकार के लोकपाल बिल में खोट है। इस लोकपाल बिल की होली देश के गांव–गांव में जलेगी।

– अन्ना हजारे

तेंदुलकर के लंबे समय तक खेलते रहने का रहस्य यही है कि उनके अंदर बच्चों की तरह उत्साह है।

– राहुल द्रविड़

संपादकीय

यह दंगा कुछ कहता है

ब्रिटेन जैसे सभ्य देश में इन दिनों दंगे हो रहे हैं। दंगे के शुरू होने के चाहे जो भी कारण रहे हों, पर एक दिन बाद ही दंगों के स्वरूप जो सामने आए वह पूरी दुनिया की आंखे खोल देने वाले हैं। ब्रिटेन के लोग दंगों में मारपीट कम लूट मार ज्यादा कर रहे हैं। कोई दुकान लूट रहा है, तो कोई किसी से पैसे छिन रहा है। कहीं कोई सिर पर भारी सामान लूट कर भाग रहा है, तो कोई खाने पर ही पिल पड़ रहा है। अचानक इस ब्रिटेन को क्या हो गया? जो आकलन आ रहे हैं, उस पर यकीन करे तो भारत जैसे देशों के लिए खतरे की जबर्दस्त घंटी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में फिर लौट आई भारी मंदी और उसके बाद पूरी दुनिया के शेयर बाजार के लुढ़कने के कारण ब्रिटेन के युवक भयभीत हो गए हैं और खुद भारी घाटा उठाने के बाद आक्रामक भी। उन्हें इस बार मंदी से निकलने का रास्ता कम दिखाई दे रहा है। इसलिए लूट मार में जुट गए हैं। जिसके हाथ जो लग रहा है वही लेकर भाग रहा है। ब्रिटेन के दंगाइयों ने सबसे अधिक रिटेल स्टोरों पर हमले किए। करीज, जेडी स्पोर्ट्स और डेबेनहम्स जैसे बड़े ब्रांड के स्टोर लूट लिए गए। जिस साम्राज्य का कभी सूरज नहीं डूबता था वह साम्राज्य आर्थिक रूप से इतना जर्जर आने लगा है कि उसके खुद के लोग खुद को ही लूटने में लग गए हैं। कहा जा रहा है कि इस दंगे में कम से कम ब्रिटेन को दस करोड़ पाउंड का नुकसान हो चुका है। लेबर पार्टी के सांसद क्रिस विलियम्सन सीधे ब्रिटेन की सरकार की आर्थिक नीतियों को इस दंगे के लिए जिम्मेदार मानते हैं उन्होंने सीधे कहा– सरकारी खर्चे में भारी कटौती और करों में वृद्धि ही लोगों में उबाल ला रहा है। यह सच है ब्रिटेन में इन दिनों फिजूल खर्ची को रोकने के नाम पर सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए हो रहे खर्चों पर भी कटौती कर दी है। बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हैं। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। यह अकेले ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों के फेल होने का परिणाम नहीं है, बल्कि ब्रिटेन पर अमरीका और यूरोप के अन्य देशों में छायी मंदी का ज्यादा असर है। 'दि टेलीग्राफ' लिखता है। वैश्विक मंदी ने फिर से सबको सड़क पर ला खड़ा किया है। अब जिसको जो मन मे आता है वह कर रहा है। युवा वर्ग सबसे ज्यादा उखड़ा हुआ है। यूरोप या अमरीका अब अपने ही किए की भरपाई कर रहा है। उनकी आर्थिक नीतियों ने समाज के सबसे बड़े वर्ग को गरीब से ज्यादा गरीब बना दिया है। 'दि गार्जियन' में नीना पवर लिखती हैं– गरीबी, बेरोजगारी और उस पर पुलिस की ज्यादती तो दंगे के लिए जिम्मेदार है ही, उससे कहीं अधिक जिम्मेदार वे आर्थिक नीतियां है जिनसे 'अमीर और अमीर' 'गरीब और गरीब' होते जा रहे हैं। ब्रिटेन के दस फीसदी लोगों के पास गरीबों के मुकाबले 100 गुनी अधिक सुख सुविधा की चीजें हैं। ब्रिटेन की सामाजिक स्थिति अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत ज्यादा खराब है। खासकर पिछले छह महीने में ब्रिटेन की माली हालात ज्यादा खराब हुई है। विकास दर लगभग नकारात्मक है। आकलन यह है कि इस साल आर्थिक विकास दर 1.1 फीसदी रहने वाली है। ऐसा अकेले ब्रिटेन में नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में है। साख संकट अमरीका से भी पहले यूरोप में ही पहुंचा। जेपी मार्गन ने यह आशंका जताई है कि अमरीका और ब्रिटेन में लगभग हर तीसरे साल मंदी का खतरा है। अभी से ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसिया अमरीका की तरह यूरोप को भी निवेश के लिए जोखिम वाले देशों में शामिल करने की तैयारी कर रही हैं। एक बड़े निवेशक का कहना है कि यह असंभव है कि अमरीका की रेटिंग घटाने के बाद ब्रिटेन समेत यूरोप की अन्य अर्थव्यवस्था की रेटिंग न घटे। साख संकट से बचने के लिए ब्रिटने के पास अन्य उपायों के साथ एक और महत्वपूर्ण उपाय यह बचता है कि वह अधिक से अधिक मुद्रा की प्रिंटिंग करे और उसका खतरा यह है कि पाउंड की कीमत कम होगी और महंगाई और बढ़ेगी। आईएमएफ ने भी चेताया है कि आने वाले दिनों में ब्रिटेन की हालत और खराब हो सकती है, क्योंकि अन्य यूरोपीय देषों में छाये साख संकट से ब्रिटेन के बैंक भी बुरी तरह प्रभावित हैं। चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। रियल एस्टेट बाजार में मुर्दनी छायी हुई है। आईएमएफ का आकलन है कि इस साल ब्रिटेन की आर्थिक विकास दर दो फीसदी से नीचे ही रहेगी। डरने की जरूरत सिर्फ ब्रिटेन और अमरीका की सरकारों को ही नहीं है। कहीं न कहीं खतरा हमारे ऊपर भी आने वाला है। खास कर हमारे निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा। अमरीकी डॉलर और ब्रिटेन के पाउंड की कीमत घटने के साथ ही हमारे निर्यातकों के भी रक्तचाप घट बढ़ रहे हैं। अब यह समय है कि अरीमका और ब्रिटेन की हालात से सबक ले और कर्ज के आधार पर बुनी अर्थव्यवस्था की अर्थनीति को विदा कर बचत आधारित अर्थव्यवस्था को लागू करे। हम आज तक बचे ही इसलिए है कि हमारी जनता आज भी बचत को सर्वाधिक महत्व देती है। नहीं हो उपभोगवादी संस्कृति का जिस तरह पालन किया गया है, वह हमें डुबोने के लिए काफी है। हालांकि वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी यह दम भरते हैं कि अमरीका और यूरोप में आए संकट का भारत पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, पर इस आशंका को वह भी खारिज नहीं करते कि यदि उनका आर्थिक संकट लंबा चला तो भारत को कुछ ठोस और त्वरित कदम उठाने पड़ेंगे। हाल के दिनों में रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति इसी बात की ओर संकेत करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए महंगाई को निमंत्रण दिया जा रहा है। हर प्रकार के कर्ज को महंगा किया गया है। ताकि मांग में कमी आए। पर इसका असर उल्टा भी हो सकता है। आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ सकती हैं। उद्योग धंधे पर खतरा मंडरा सकता है और विकास दर भी प्रभावित हो सकता है।

महंगाई पर सरकार का शुतुरमुर्गी रवैया

बढ़ती महंगाई से बौखलाई सरकार इसे रोकने के लिए कोई भी कारगर कदम नहीं उठा पा रही है। यों तो पिछले तीन सालों से महंगाई लगातार बढ़ ही रही है, लेकिन पिछले एक साल से यह सभी हदें पार करते हुए आम लोगों का जीवन दूभर बना रही है। महंगाई में सर्वाधिक चोट अति गरीब आदमी पर पड़ रही है, क्योंकि उसके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थ मसलन अनाज, दालें, खाद्य तेल और फल–सब्जियां विशेषतौर पर महंगे हुए हैं।

■ डा. अश्विनी महाजन

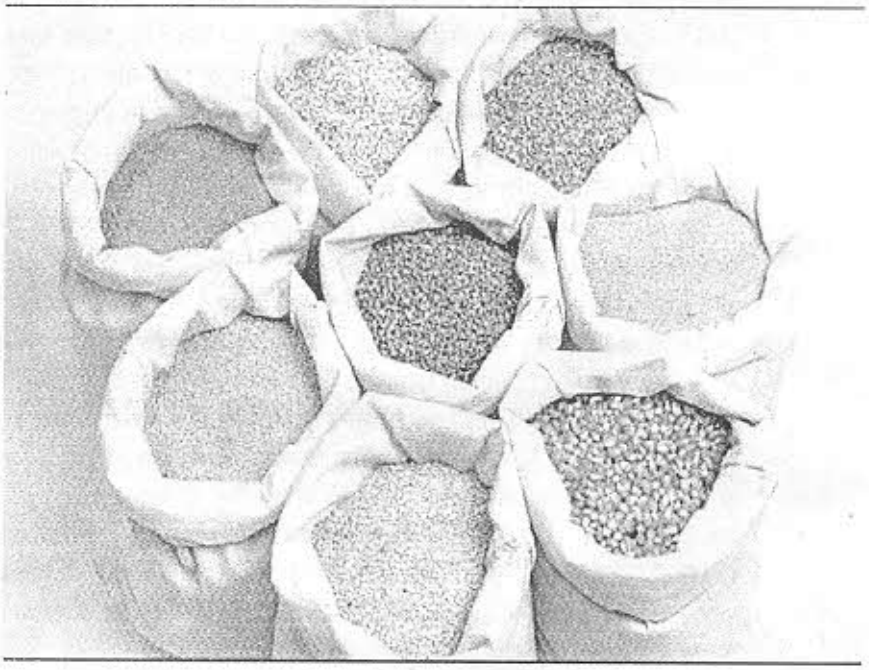

बढ़ती महंगाई से बौखलाई सरकार इसे रोकने के लिए कोई भी कारगर कदम नहीं उठा पा रही है। यों तो पिछले तीन सालों से महंगाई लगातार बढ़ ही रही है, लेकिन पिछले एक साल से यह सभी हदें पार करते हुए आम लोगों का जीवन दूभर बना रही है।

इस महंगाई में सर्वाधिक चोट अति गरीब आदमी पर पड़ रही है, क्योंकि उसके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थ मसलन अनाज, दालें, खाद्य तेल और फल–सब्जियां विशेषतौर पर महंगे हुए हैं।

महंगाई के सामने लाचार सरकार हर बार रिजर्व बैंक का द्वार ठोंकते हुए उसे ही बाध्य कर रही है कि वह येन–केन–प्रकारेण महंगाई को काबू करने का प्रयास करे। इस कवायद में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपोरेट और रिवर्स रेपोरेट में .5 बेसिस प्वाइंट यानी आधा फीसदी की वृद्धि करते हुए उन्हें क्रमशः आठ और सात प्रतिशत कर दिया है।

रेपोरेट वह ब्याज दर होती है, जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। रिवर्स रेपोरेट वह ब्याज दर होती है, जिस पर बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं। ब्याज दरों में यह वृद्धि 1 अप्रैल 2011 से शुरू हुए वित्तीय वर्ष में तीसरी वृद्धि है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में आठ बार वृद्धि की थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मात्र 16 महीनों में 11 बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी सीधे तौर पर संकुचनवादी मौद्रिक नीति मानी जा सकती है।

सामान्य तौर पर माना जाता है कि महंगाई का प्रमुख कारण मांग में वृद्धि होता है। वस्तुओं की कम उपलब्धता और बढ़ती मांग कीमतों पर दबाव बनाती है, इसलिए रिजर्व बैंक परंपरागत तौर पर ब्याज दरों में वृद्धि कर कीमतों को शांत करने का प्रयास करता है।

लेकिन विडंबना यह है कि इतने कम समय में ब्याज दरों में भारी वृद्धि के बावजूद कीमत वृद्धि थमने का नाम नहीं ले रही और जुलाई माह तक आते–आते पिछले वर्ष की तुलना में महंगाई 9.5 प्रतिशत बढ़ गई। खाद्य पदार्थों में यह वृद्धि 12.3 प्रतिशत की थी, लेकिन रिजर्व बैंक की मृग–मरीचिका का कोई अंत नहीं है।

ऐसा कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में और अधिक वृद्धि भी कर सकता है। ब्याज दरों में वृद्धि के खतरे आज बढ़ती आमदनी के युग में मध्यम वर्ग, विशेष तौर पर मध्यवर्गीय युवा अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की जुगत में रहता है। ऐसे में अच्छा और अपना घर, कार या मोटर साइकिल और जीवन के

अन्य साजो–समान खरीदने के लिए वह बैंकों से उधार लेता है और उसे किश्तों यानी ईएमआइ से चुकाता है।

पश्चिमी देशों से आई इस पद्धति से जीवन स्तर तो बेहतर हुआ, लेकिन आम आदमी की देनदारियां भी बढ़ गई हैं। यह देनदारियां सामान्यतः स्थिर ब्याज दर पर आधारित नहीं होतीं। बढ़ते ब्याज दर से ईएमआई भी बढ़ जाती है। ऐसे में मध्यम वर्ग की ईएमआई बढ़ते जाने से रोजमर्रा के लिए उसके पास आमदनी बहुत कम बचती है।

ब्याज दरों का पेच यदि पिछले दस वर्षों का हिसाब देखें तो पाते हैं कि कृषि की विकास दर कम होने के बावजूद अन्य क्षेत्रों में आमदनियां बढ़ीं और अर्थव्यवस्था की सकल संवृद्धि दर 8 से 9 प्रतिशत के बीच रही। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इस दशक के पहले 6–7 वर्षों तक कीमतों में वृद्धि को काफी हद तक काबू में रखा जा सका। कीमतों में अपेक्षित नियंत्रण के चलते ब्याज दरें घटने लगीं। हालांकि घटती ब्याज दरों ने एक ऐसे वर्ग, जो ब्याज की आय पर आधारित था, को प्रभावित तो किया, लेकिन घटती ब्याज दरों ने देश में घरों, कारों, अन्य उपभोक्ता वस्तुओं आदि की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि की। कम ब्याज दरों के चलते सरकार द्वारा अपने पूर्व में लिए गए ऋणों की ब्याज अदायगी पर भी अनुकूल असर पड़ा।

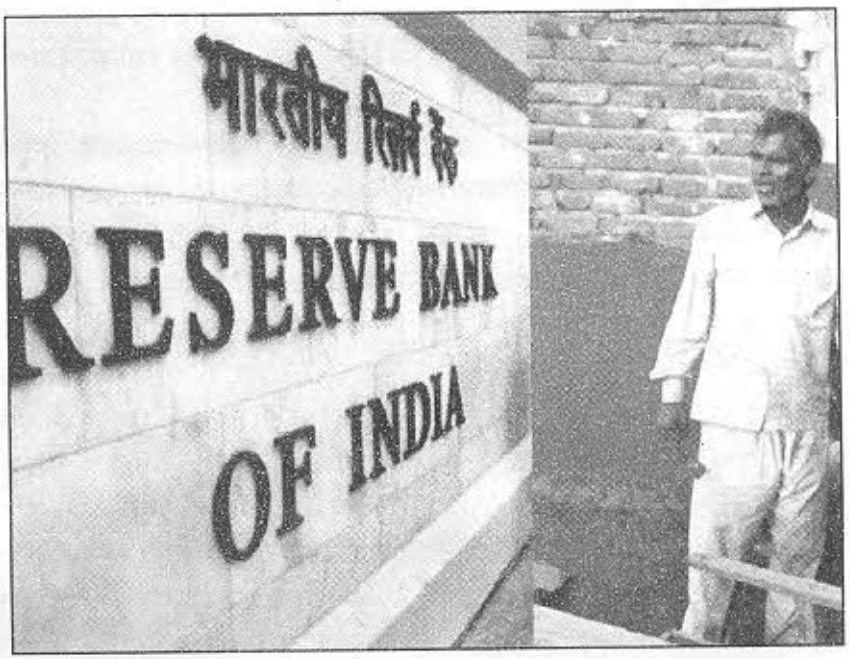

हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में तेजी से विकास होना शुरू हुआ और देश–दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया।

वर्तमान में देश में महंगाई बढ़ने के दो प्रमुख कारण हैं। एक खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि और दूसरा पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत। खाद्य पदार्थों की महंगाई बाजार में तरलता अधिक होने के कारण नहीं, बल्कि खाद्य पदार्थों की कमी के कारण है। इसलिए खाद्य मुद्रा स्फीति को काबू में रखने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, न कि ब्याज दरों को।

कहा जा सकता है कि भारत की आर्थिक संवृद्धि की गाथा में ब्याज दरों के घटने की एक प्रमुख भूमिका रही है। विकास की ऊंची दर के लिए जरूरी है कि ब्याज दरों को नीचा रखा जाए, लेकिन बढ़ती महंगाई के दौर में यह बात मुश्किल हो जाती है।

एक ओर तो रिजर्व बैंक को महंगाई पर काबू करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करनी पड़ती है तो दूसरी ओर ब्याज अर्जित करने वाले वर्ग को बचत करने और उसे बैंकों के पास जमा करने हेतु प्रेरित करने के लिए ब्याज दर को महंगाई की दर से ऊंचा रखना पड़ता है। इसलिए देश में आर्थिक संवृद्धि की दर को तेज करने के लिए ब्याज दरों को घटाना जरूरी है और ब्याज दरों को घटाने के लिए महंगाई पर काबू पाना जरूरी है। बढ़ेगा ब्याज तो रुकेगी महंगाई?

पिछले कुछ समय का अनुभव यह बताता है कि ब्याज दरों में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि नहीं रुक रही। वर्तमान में देश में महंगाई बढ़ने के दो प्रमुख कारण हैं। एक खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि और दूसरा पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत। खाद्य पदार्थों की महंगाई बाजार में तरलता अधिक होने के कारण नहीं, बल्कि खाद्य पदार्थों की कमी के कारण है।

इसलिए खाद्य मुद्रा स्फीति को काबू में रखने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, न कि ब्याज दरों को।

पिछले एक वर्ष में सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को बाजार पर छोड़ दिए जाने के कारण, उनमें लगातार वृद्धि हो रही है, जो महंगाई का मुख्य सबब बन रही है। ब्याज दरों को बढ़ाने से महंगाई के इस कारण पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए महंगाई के कारणों की जांच करते हुए उस पर प्रभावी नियंत्रण देश को आर्थिक संवृद्धि और विकास की पटरी पर रखने के लिए बहुत जरूरी है। मांग में कमी या आपूर्ति में वृद्धि! ब्याज दर बढ़ाकर या बैंकों के रिजर्व बढ़ाकर रिजर्व बैंक यह कोशिश कर सकता है कि महंगाई की दर घट जाए।

जब रिजर्व बैंक ब्याज दर बढ़ाता है तो उधार की लागत बढ़ जाती है, जिससे लोग कम उधार लेते हैं। ऐसे में कारों, घरों और अन्य साजो–समान की मांग घटने से उनका उत्पादन भी घट जाता है। इस प्रकार आर्थिक संवृद्धि को धक्का पहुंचता है।

हालांकि अभी तक ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद ऑटोमोबाइल आदि की मांग में कोई विशेष कमी दिखाई नहीं देती, लेकिन तमाम रियायतों के बावजूद गृह निर्माण क्षेत्र में मंदी साफ दिखाई देती है। फिर भी इन सब के बावजूद कीमतें थम नहीं रहीं। लेकिन अगर सरकार पूर्ति पक्ष की तरफ ध्यान दे तो कीमतों में वृद्धि भी थम सकती है और ब्याज दरों को भी सीमा में रखा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार कृषि विकास की ओर उचित ध्यान दे।

पिछले लगभग दो दशकों से चल रही कृषि की अनदेखी ने कृषि विकास को बाधित किया है। खाद्यान्नों, दालों, तिलहनों और फल–सब्जियों का उत्पादन थम गया है। बढ़ती आमदनियों के चलते खाद्य पदार्थों की मांग तो बढ़ रही है, लेकिन पूर्ति नहीं। ऐसे में पिछले लगभग पांच वर्षों में खाद्य पदार्थों की महंगाई की दर अन्य पदार्थों की तुलना में दोगुनी से भी अधिक रही है। ऐसे में नीति निर्माता कृषि की अनदेखी समाप्त कर किसानों को उत्पादन बढ़ाने हेतु सिंचाई, उर्वरक और अच्छे बीजों की व्यवस्था समेत सभी प्रोत्साहन प्रदान करें, तभी महंगाई का इलाज हो सकता है।

रिजर्व बैंक के बार–बार ब्याज दरों को बढ़ाने की कार्रवाई ने अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया है। इसके कारण सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 के लिए आर्थिक संवृद्धि की अपेक्षित दर भी 8.5 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दी गई है। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस वर्ष आर्थिक संवृद्धि की दर इससे भी कम हो सकती है। हर बार रिजर्व बैंक को ही महंगाई रोकने का जिम्मा देना न केवल अर्थव्यवस्था में मंदी लाएगा, बल्कि भविष्य में महंगाई को रोकने के प्रयासों की कारगरता पर भी असर पड़ेगा। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

मंदी

कर्ज के भँवर में अमरीका

अमेरिका आज कर्ज के जिस जाल में फंसा है उससे निकलने का कोई उपाय उसे दिख नहीं रहा है। अमेरिका के आर्थिक संकट का असर भारत पाकिस्तान जैसे एशियाई देशों के साथ–साथ पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। वर्तमान वैश्विक युग में दुनियां के देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसका असर उन देशों पर अधिक पड़ेगा जिनके साथ अमेरिका का व्यापार अधिक होता है. . .

■ निरंकार सिंह

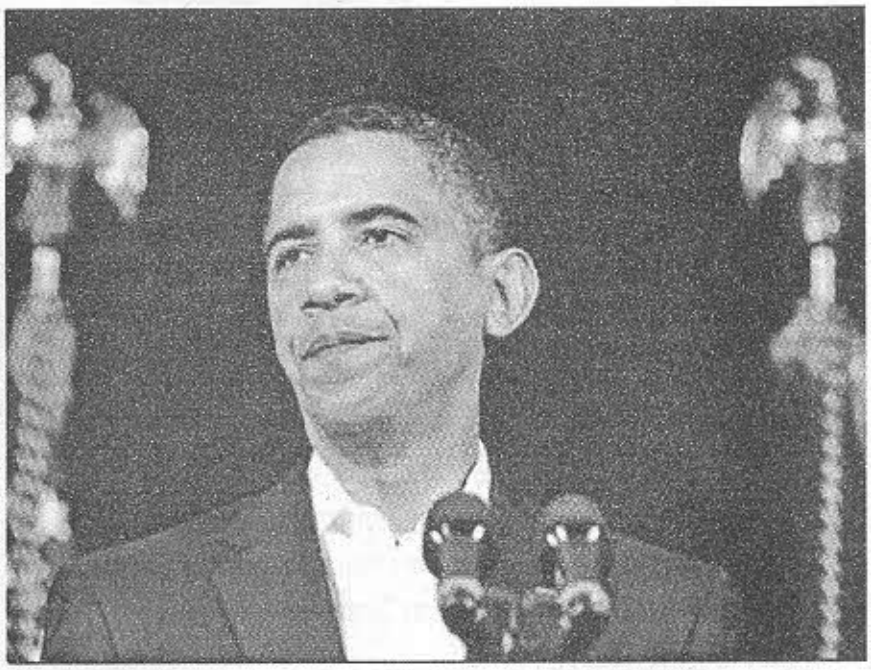

अमेरिकी सरकार का घरेलू कर्ज इतना ज्यादा है कि हर सप्ताह करीब 90 अरब डॉलर की देनदारी (अगस्त में 500 अरब डॉलर) निकल रही है। अमेरिका को अपने जीडीपी अनुपात में करीब 18 फीसदी राशि बकाया कर्ज के पुनर्वित्त यानी रिफाइनेंस के लिए चाहिए। इसका मतलब है कि अमेरिका बड़े ऋण जाल में फंस चुका है। अमेरिका के लिए वापसी अब लगभग नामुमकिन है और उबरने का हर इलाज उसे कमजोर ही करेगा।

अमेरिका का कर्ज संकट दुनिया के लिए एक बड़े खतरे का संकेत है। हालांकि उसका तात्कालिक कर्ज संकट रिपब्लिकनों और डेमोक्रेट्स की आम सहमति से टल गया है, लेकिन खतरा समाप्त नहीं हुआ है। समझौते के पहले चरण में कर्ज लेने की सीमा में 900 बिलियन डॉलर की छूट के एवज में सरकारी खर्च में उतने की ही कटौती की जाएगी। दूसरे चरण के तहत कांग्रेस की एक सुपर कमेटी नवंबर तक 1.5 अरब डॉलर तक की बचत के उपाय सुझाएगी।

अमेरिका आज कर्ज के जिस जाल में फंसा है उससे निकलने का कोई उपाय उसे दिख नहीं रहा है। अमेरिका के आर्थिक संकट का असर भारत पाकिस्तान जैसे एशियाई देशों के साथ–साथ पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। वर्तमान वैश्विक युग में दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसका असर उन देशों पर अधिक पड़ेगा जिनके साथ अमेरिका का व्यापार अधिक होता है। अमेरिका का आर्थिक संकट दुनिया के कई देशों को मंदी की चपेट में ला सकता है। अमेरिकी सरकार का घरेलू कर्ज इतना ज्यादा है कि हर सप्ताह करीब 90 अरब डॉलर की देनदारी (अगस्त में 500 अरब डॉलर) निकल रही है। अमेरिका को अपने जीडीपी अनुपात में करीब 18 फीसदी राशि बकाया कर्ज के पुनर्वित्त यानी रिफाइनेंस के लिए चाहिए। इसका मतलब है कि अमेरिका बड़े ऋण जाल में फंस चुका है।

अमेरिका के लिए वापसी अब लगभग नामुमकिन है और उबरने का हर इलाज उसे कमजोर ही करेगा। अमेरिका में मंदी की शुरुआत वर्ष 2008 से हुई थी। इस मंदी की चपेट में जब अमेरिका के बड़े–बड़े कारपोरेट एक–एक करके धराशायी होने लगे तो अमेरिकी सरकार ने इनके लिए अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए। उसने अरबों डॉलर के बेलआउट पैकेज देकर बैंक ऑफ अमेरिका,

अब अमेरिका चाहे कर्ज की सीमा बढ़ाए या न बढ़ाए दोनों ही हालत में अमेरिका की ट्रिपल ए रेटिंग घट जाएगी। अमेरिका की रेटिंग में कमी एक ऐतिहासिक फैसला होगा, क्योंकि अमेरिकी बांड कर्ज के बाजार में सोने से ज्यादा खरे और सबसे मजबूत जमानत माने जाते हैं। रेटिंग घटते ही अमेरिका में ब्याज दर बढ़ेगी जो कर्ज के पहाड़ को काटने की राह और मुश्किल कर देगी।

सिटीग्रुप और एआईजी जैसे वित्तीय संस्थानों के साथ ही ऑटो दिग्गज जनरल मोटर्स जैसी कई कंपनियों को बचाया। इस राहत पैकेज से अमेरिकी कारपोरेट तो मंदी के भंवर से निकल आया, मगर अपनी अर्थव्यवस्था को उबारने की कोशिश में अमेरिकी सरकार ने खर्चे इतने ज्यादा बढ़ा दिए कि कर्जे की तय सीमा भी पार होने वाली है। अमेरिकी संविधान में कर्ज की तय सीमा 14,300 अरब डॉलर है। भारतीय मुद्रा में यह रकम 6,34,900 अरब रुपये बैठती है।

अब अमेरिका चाहे कर्ज की सीमा बढ़ाए या न बढ़ाए दोनों ही हालत में अमेरिका की ट्रिपल ए रेटिंग घट जाएगी। अमेरिका की रेटिंग में कमी एक ऐतिहासिक फैसला होगा, क्योंकि अमेरिकी बांड कर्ज के बाजार में सोने से ज्यादा खरे और सबसे मजबूत जमानत माने जाते हैं। रेटिंग घटते ही अमेरिका में ब्याज दर बढ़ेगी जो कर्ज के पहाड़ को काटने की राह और मुश्किल कर देगी। इसका असर उसके व्यापार पर पड़ेगा। अमेरिका का वार्षिक बजट घाटा डेढ़ खरब डॉलर है। कर्ज संकट से निपटने के लिए कर्ज लेने की क्षमता बढ़ाने का काम अमेरिकी सीनेट में आमतौर पर होता रहा है, लेकिन इस बार रिपब्लिकन पार्टी कर्ज बढ़ाने के मुद्दे पर कड़ा रुख अपना रही है।

रिपब्लिकन चाहते हैं कि सरकार टैक्स में कोई बढ़ोतरी न करे, जबकि डेमोक्रेट का मानना है कि गरीबों, बूढ़ों और अन्य लोगों को पेंशन योजना के लिए पैसा टैक्स बढ़ोतरी से हासिल किया जाए। अमेरिकी सरकार एक निश्चित सीमा तक कर्ज लेने के कानूनी प्रावधान से बंधी है। इससे प्राप्त धन से ही सरकार अपने नियमित खर्चों का भुगतान करती है। इनमें सेना का वेतन, वर्तमान कर्ज पर ब्याज की रकम और स्वास्थ्य सुविधाओं पर होने वाला खर्च भी शामिल है। उसकी कर्ज लेने की 14.3 अरब डॉलर की सीमा मई में ही खत्म हो चुकी थी।

वित्त मंत्री टिमोथी गीथनर ने सरकारी पेंशन योजनाओं के लिए किए जाने वाले भुगतान को आगे बढ़ाने के लिए समय सीमा को दो अगस्त तक बढ़ाने जैसे कदमों का सहारा लिया था। सभी सरकारी कर्जों को अमेरिकी संविधान के तहत संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है। कर्ज लेने की सीमा पहली बार 1917 में शुरू की गई थी, ताकि सरकार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने खर्चे चला सके। उसके बाद यह सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। आमतौर पर यह महज एक औपचारिकता ही होती है। इससे पहले कांग्रेस सरकार के खर्चों और टैक्स को तय करती रही है।

ओबामा प्रशासन एक ऐसी असहज स्थिति का सामना कर रहा है जिसमें उसके खर्चे उपलब्ध आमदनी से कहीं ज्यादा हैं। वित्तीय संकट और अमेरिका की दुर्बल अर्थव्यवस्था की वजह से सरकार के खर्चों में तो वृद्धि हुई जबकि टैक्स से मिलने वाला राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ। परिणामस्वरूप सरकार का घाटा बढ़ गया। प्रतिनिधि सभा पर प्रभुत्व रखने वाले रिपब्लिकन सांसदों का कहना है कि वित्तीय घाटा काबू किया जाए।

दोनों ही मानते हैं कि घाटे में कमी करना जरूरी है, लेकिन दोनों पार्टियों की आर्थिक नीतियां अलग हैं। सीनेटर के एक समूह ने खर्चों में कटौती और टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। जहां रिपब्लिकन सांसद खर्च में और अधिक कटौती की मांग कर रहे हैं, वहीं डेमोक्रेट चाहते हैं कि खर्चों में कटौती न हो, बल्कि कारपोरेट सेक्टर पर अधिक टैक्स लगाकर कर्ज संकट से उबरने का रास्ता निकाला जाए।

अमेरिकी सीनेट ने देश की कर्ज सीमा को बढ़ाने वाला बिल खारिज कर दिया था। डेमोक्रेटिक पार्टी की बहुमत वाली सीनेट में इस बिल के गिरने की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। पर अब उसने सरकारी खर्चों में कटौती की शर्त के साथ कर्ज की सीमा बढ़ाए जाने पर सहमति प्रदान कर दी है। गौरतलब है कि अगर दो अगस्त तक ये मसला नहीं सुलझता तो अमेरिका में नकदी की उपलब्धता का संकट पैदा हो जाता। साथ ही अमेरिका की कर्ज लौटाने की क्षमता भी प्रभावित होगी। इस बिल को लेकर रिपब्लिकन और डेमाक्रेटिक पार्टी के बीच भारी मतभेद रहे। रिपब्लिकन पार्टी चाहती है कि अल्पकालिक कर्जों की सीमा 900 बिलियन डॉलर तक की जाए, लेकिन डेमोक्रेट्स इस सीमा को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चेतावनी दी थी कि अगर राजनीतिक दलों ने देश के कर्ज संकट को निपटाने के उपायों पर जल्द समझौता नहीं किया तो सभी अमेरिकी लोगों को परेशान होना पड़ेगा। उन्होंने अमेरिकी लोगों से आग्रह किया था कि वे राजनेताओं पर समय रहते अपने मतभेद दूर करने का दबाव

बढ़ाएं, क्योंकि इस संकट के कारण अमेरिका की साख पर असर पड़ सकता है। ओबामा ने इस बारे में दोनों पक्षों से समझौता कर किसी तरह सुलह पर पहुंचने का आह्वान किया था। फिलहाल यह संकट टल गया है पर चिंता बरकरार है।

अमेरिकी मंदी का खतरा यूरोप तक पहुंच गया और अब एशियाई देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई प्रमुख क्रिस्टीना लगार्द ने यूरोपीय नेताओं को चेतावनी दी है कि यूरो जोन की आर्थिक समस्याओं की वजह से वहां सामाजिक अस्थिरता का खतरा पैदा हो सकता है। ग्रीस, पुर्तगाल और आयरलैंड में ऋण संकट के बाद इटली और स्पेन के ऊपर भी इसका खतरा मंडरा रहा है।

हाल ही में ग्रीस के लिए जारी किए गए 96 खरब डॉलर के राहत पैकेज के बावजूद आर्थिक संकट का खतरा खत्म नहीं हुआ है। मध्य–पूर्व के देशों और उत्तर अफ्रीका में राजनीतिक उथल–पुथल जैसी सामाजिक समस्याएं भी इन उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय हैं।

हाल ही में ग्रीस के लिए जारी किए गए 96 खरब डॉलर के राहत पैकेज के बावजूद आर्थिक संकट का खतरा खत्म नहीं हुआ है। मध्य–पूर्व के देशों और उत्तर अफ्रीका में राजनीतिक उथल–पुथल जैसी सामाजिक समस्याएं भी इन उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय हैं। जहां एक तरफ युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं तो दूसरी ओर बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य और पेंशन सुविधाओं को बचाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इन दोनों ही समस्याओं के चलते पीढ़ियों के बीच संघर्ष का सामना दिख सकता है। वास्तव में आज दुनिया एक नए तरह के वैश्विक संकट की ओर बढ़ रही है जिसकी सबसे ज्यादा कीमत गरीब देशों को चुकानी पड़ रही है। ❑

ताकतवर है अपना शेयर बाजार

भारतीय शेयर बाजार में सॉफ्टवेयर उद्योग के शेयरधारकों और लैदर, जैम एंड ज्वैलरी उद्योग के निवेशकों को डरने की जरूरत है पर बाकी उद्योगों और कंपनियों के निवेशकों को डरने की जरूरत नहीं है। पर होता इसका उलटा है। जब निवेशकों को डरने की जरूरत होती है, तब वो बहुत बहादुर बनकर सौदे करते हैं और जब उन्हे बहादुर बनकर सौदे करने चाहिए, तब वह डर जाते हैं। इसलिए शेयर बाजार में संभावनाओं के आधार पर निवेश करने वाले निवेशक आम तौर पर धोखा खाते हैं। फिलहाल भारतीय शेयर बाजार की तरफ से आने वाला संदेश साफ है– डरना मना है।

■ आलोक पुराणिक

अमेरिका ग्लोबल पावर है, यह बात सिर्फ उसके अफगानिस्तान और इराक के हमलों से ही पता नहीं चलती। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की क्रेडिट रेटिंग गिरने से इस समय पूरी दुनिया में फिर हड्कंप मच गया है। हड़कंप में आमतौर पर हर कोई भागने की कोशिश करता है। और वास्तविकता क्या है या सच में क्या हुआ, यह जानने की फुर्सत कम ही लोगों के पास होती है। और फुर्सत हो भी तो साहस जुटाने का काम और भी मुश्किल होता है। विश्व बाजार में हाल के घटनाक्रम में यही हुआ है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के डूबने की दहशत में विश्व भर के स्टॉक बाजार डूब गये हैं। भारतीय शेयर बाजारों का भी यही हाल रहा है।

9 अगस्त, 2011 को बंद हुए शेयर कारोबार में मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 132.27 अंक गिरकर 16,857.91 के अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी सूचकांक 45.65 अंक गिरकर 5072.85 पर बंद हुआ। सेंसेक्स इस दिन सुबह के कारोबार में करीब पांच सौ अंक गिर गया था। पर बाद में यह संभल गया और गिरावट सिर्फ 132.27 अंक तक सीमित रह गयी।

इस कारण सोने का भाव लगातार ऊपर जा रहा है। वह छब्बीस हजार रुपये प्रति दस ग्राम के भाव की ओर अग्रसर है। दूसरी ओर कच्चे तेल के दामों में लगातार कमी आ रही है। कच्चा तेल पिछले दस महीनों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। इसकी वजह साफ है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी का मतलब यह है कि वहां मोटर कारों की मांग कम हो जाएगी। लोग रकम बचाने के चक्कर में पेट्रोल, डीजल वगैरह पर कम खर्च करेंगे। इस समय अमेरिका कच्चे तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सबसे बड़े उपभोक्ता के बाजार में ठंडक हो, तो साफ तौर पर तेल के बाजार में भी कमी आएगी। सो तेल के भाव लगातार कम हो रहे हैं पर इन सब बातों का मतलब

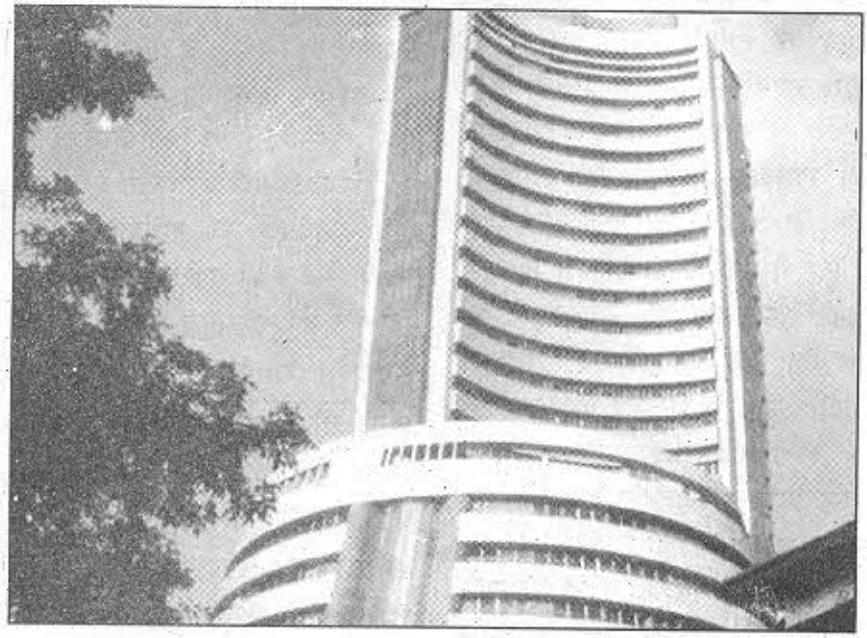

शेयर बाजारों का इतिहास बताता है कि अति प्रतिक्रिया के समय शेयर बाजार में जो तार्किक दृष्टिकोण अपनाते हैं, वे फायदे में रहते हैं। पर सच यह भी है ऐसे विकट माहौल में तार्किक प्रतिक्रिया बनाये रखना बहुत ही मुश्किल और हिम्मत का काम है। सवाल यह है कि भारतीय शेयर बाजारों पर अमेरिकी घटनाक्रम का क्या असर होगा?

यह नहीं है कि समूची भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय शेयर बाजारों पर भी खराब असर पड़ेगा।

फिलहाल तो भारतीय बाजारों ने गहरा नकारात्मक रुख दिखाया है पर इसका मतलब यह नहीं है कि आने वाले दिनों में भी भारतीय शेयर बाजार नीचे ही जाएंगे। शेयर बाजार आम तौर पर जल्दी में अति प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें संतुलित होने में समय लगता है। अमेरिका के घटनाक्रम के प्रति भारतीय शेयर बाजारों ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वह अतिरेक की प्रतिक्रिया है।

कुल मिलाकर देखा जाए तो समूचे घटनाक्रम का भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय उद्योग जगत पर सिर्फ नकारात्मक असर ही नहीं है। इसलिए शेयर बाजार में अपने शेयर तेजी से बेचकर निकलने वालों को बाद में पता लगेगा कि उन्होंने बहुत घाटे के सौदे किये। इस समय शेयर बाजार में बतौर खरीदार जाने वाले निवेशक भविष्य में बहुत फायदे में होंगे, ऐसी उम्मीद भी की जा सकती है।

शेयर बाजारों का इतिहास बताता है कि अति प्रतिक्रिया के समय शेयर बाजार में जो तार्किक दृष्टिकोण अपनाते हैं, वे फायदे में रहते हैं। पर सच यह भी है ऐसे विकट माहौल में तार्किक प्रतिक्रिया बनाये रखना बहुत ही मुश्किल और हिम्मत का काम है।

सवाल यह है कि भारतीय शेयर बाजारों पर अमेरिकी घटनाक्रम का क्या असर होगा? पहला असर तो बहुत साफ है कि जो उद्योग अमेरिकी बाजार पर आश्रित हैं, फिलहाल उनकी बेहतर होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का साठ प्रतिशत निर्यात अमेरिकी बाजारों में होता है। यानी सॉफ्टवेयर उद्योग को नये बाजार तलाशने होंगे।

अमेरिका पर निर्भरता ने एक दौर में सॉफ्टवेयर उद्योग को बहुत मोटा मुनाफा कमवाया है। और अब कम मुनाफे या घाटे का वक्त है। तो साफ्वेयर उद्योग की स्थिति खराब होने की आशंका है। और यह साफ भी हुआ है कि सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयरों में बेतहाशा गिरावट आई है। यह भी संभव है कि साफ्टवेयर क्षेत्र में भरतियां ज्यादा ना हों। उल्टे यह उद्योग छंटनी की ओर भी जा सकता है। इसके अलावा, हीरे और चमड़ा उद्योग के अमेरिकी निर्यात पर भी असर पड़ सकता है।

मंदी में फंसी अमेरिकी अर्थव्यवस्था हीरे और चमड़े के कपड़ों को बड़े पैमाने पर खरीदेगी, ऐसा नहीं माना जा सकता है। पर जिन उद्योगों का ताल्लुक अमेरिका से नहीं है या जिनका ताल्लुक भारतीय कारकों से हैं, उनकी सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।

जैसे अभी देश की सबसे बड़ी कार कंपनी ने बताया है कि एक खास कार की बुकिंग ने रिकार्ड बना दिया। 40,000 कारें पहले ही बुक हो गयीं। यह ऐतिहासिक है। हमारा ऑटोमोबाइल बाजार तो घरेलू कारकों से ठंडक में है। यहां ब्याज की दरें लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए कार खरीदना महंगा हो रहा है। पर अपने यहां बढ़ती महंगाई के लिए अच्छी खबर अमेरिकी संकट से आयी लगती है। कच्चे तेल के भाव दस महीनों के न्यूनतम स्तर पर आ गये हैं।

चर्चा है कि अपने यहां पेट्रोल डेढ़ रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हो जायेगा। यह भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए ठीक होने के साथ–साथ पूरी अर्थव्यवस्था के अनुकूल होगा। तेजी से बढ़ती ईएमआई की हालत सुधरेगी। ये सारी बातें भारतीय अर्थव्यवस्था के हित में ही हैं।

इसके अलावा, एक सवाल फिलहाल महत्वपूर्ण है। वह यह कि पूरे विश्व में अमेरिका अगर निवेश के लिहाज से असुरक्षित देश बन रहा है, तो फिर कौन से देश हैं जहां तमाम विदेशी वित्तीय संस्थानों को और दूसरे निवेशकों को निवेश की संभावनाएं दिखती हैं। चीन इस तरह की अर्थव्यवस्था है पर वहां लोकतंत्र का न होना एक बड़ी बाधा है। फिर तो भारतीय अर्थव्यवस्था ही इस मामले में बेहतर स्थिति में है।

यानी पूरे विश्व से तमाम विदेशी निवेशक और संस्थान निवेश के लिए भारत आ सकते हैं, इसकी उम्मीद की जा सकती है। यानी वर्तमान परिस्थितियों में भारत का स्टॉक बाजार बेहतर निवेश विकल्प के तौर पर उभरेगा। इसके चलते भारतीय स्टॉक बाजारों में विदेशी निवेश बढ़ेगा। कुल मिलाकर स्टॉक बाजारों के दृष्टिकोण से देखें, तो भारतीय शेयर बाजार में सॉफ्टवेयर उद्योग के शेयरधारकों और लैदर, जैम एंड ज्वैलरी उद्योग के निवेशकों को डरने की जरूरत है पर बाकी उद्योगों और कंपनियों के निवेशकों को डरने की जरूरत नहीं है।

पर होता इसका उलटा है। जब निवेशकों को डरने की जरूरत होती है, तब वो बहुत बहादुर बनकर सौदे करते हैं और जब उन्हे बहादुर बनकर सौदे करने चाहिए, तब वह डर जाते हैं। इसलिए शेयर बाजार में संभावनाओं के आधार पर निवेश करने वाले निवेशक आम तौर पर धोखा खाते हैं। फिलहाल भारतीय शेयर बाजार की तरफ से आने वाला संदेश साफ है– डरना मना है। ❑

असमानता पर उदासनीता

श्रम बाजार में प्रवेश करने वालों की संख्या में प्रति वर्ष लगभग 40 लाख की वृद्धि हो रही है। अतः जितने व्यक्तियों को उच्चकोटि के रोजगार मिल रहे हैं, गरीबों की संख्या में उससे दस गुना वृद्धि हो रही है। ये रोजगार असमानता की समस्या का समाधान नहीं हैं। तथापि भविष्य इसी प्रकार के रोजगारों का है। इनमें तीव्र वृद्धि की जरूरत है। ऐसा आम जनता को अच्छी शिक्षा पहुंचाने से ही संभव होगा।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

संप्रग सरकार अति प्रसन्न है। हाल में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार गरीबी में गिरावट आई है। 2005 में 37 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे थे, जबकि 2010 में इनकी संख्या घटकर 32 प्रतिशत रह गई है। इसे खुले बाजार की आर्थिक नीतियों का परिणाम बताया जा रहा है, लेकिन दो समस्याएं हैं। पहली यह कि गरीबी में गिरावट की गति धीमी हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रो. प्रणब बर्धन के अनुसार सत्तर और अस्सी के दशक में गिरावट की गति अधिक थी, जो आर्थिक सुधारों के बाद धीमी हुई है।

दूसरी समस्या है कि असमानता में भारी वृद्धि हुई है। एशियाई विकास बैंक द्वारा किए गए अध्ययन में बताया गया है कि आर्थिक सुधारों से पहले असमानता घट रही थी। 1994 के बाद इसमें वृद्धि हो रही है। योजना आयोग के सदस्य प्रो. अभिजित सेन कहते हैं कि असमानता बढ़ रही है और संपत्ति के भद्दे संग्रह को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है।

चुनिंदा अमीर लोगों के पास निजी विमान जैसी विलासिता की महंगी वस्तुओं का भंडार बढ़ता जा रहा है, जबकि गरीब की हालत में मामूली सुधार हुआ है। कस्बे में मर्सिडीज कार दिखने लगे तो स्कूटर का सुख जाता रहता है। इसी प्रकार अमीरी में भारी बढ़त के सामने गरीब की स्थिति में जो सुधार हुआ है वह धूमिल पड़ जाता है। आर्थिक सुधारों के पूर्व असमानता नियंत्रण में थी, परंतु आर्थिक विकास दर न्यून थी। आर्थिक सुधारों के बाद आर्थिक विकास दर में वृद्धि हुई है, परंतु असमानता में भी उतनी ही तीव्रता से वृद्धि हो रही है। गरीबी की गिरावट की चाल भी घट रही है। अतः संप्रग सरकार को इस गिरावट से प्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है। दरअसल, हम गरीबी के कुएं से निकल कर असमानता की खाई में गिर रहे हैं।

असमानता का पहला कारण कल्याणकारी योजनाओं की घटती कार्यकुशलता है। वर्तमान समय में गरीब को आगे बढ़ाने में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। गरीब सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं। इनमें फीस नहीं भरनी पड़ती, साथ ही

असमानता का पहला कारण कल्याणकारी योजनाओं की घटती कार्यकुशलता है। वर्तमान समय में गरीब को आगे बढ़ाने में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। गरीब सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं। इनमें फीस नहीं भरनी पड़ती, साथ ही मुफ्त में भोजन और किताबें भी मिल जाती हैं, पर इन स्कूलों के रिजल्ट खराब होते जा रहे हैं। फलस्वरूप गरीब अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

मुफ्त में भोजन और किताबें भी मिल जाती हैं, पर इन स्कूलों के रिजल्ट खराब होते जा रहे हैं। फलस्वरूप गरीब अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का कहना है कि भारत के मानव विकास सूचकांक में शिक्षा की असमानता का संज्ञान लेने पर 43 प्रतिशत की गिरावट आती है। दूसरे देशों की तुलना में भारत में यह असमानता अधिक है। दूसरी तरफ रोजगार गारंटी एवं ऋण माफी से लाभ हुआ है।

मेरा आकलन है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों के घटिया क्रियान्वयन से जितना नुकसान हुआ है उसकी आंशिक भरपाई ही रोजगार गारंटी से हुई है। कुल मिलाकर यह घाटे का सौदा रही है। विशेष यह कि इन खर्चों को वहन करने के लिए सरकार ने टैक्स अधिक वसूल किया है। दर घटाने के बावजूद टैक्स की अधिक वसूली का कारण है कि अमीरियत बढ़ी है। देश में बड़ी संख्या में अरबपति पैदा हो गए हैं। बड़ी कंपनियों के अधिकारियों को करोड़ों रुपये का वार्षिक पैकेज दिया जा रहा है। यानी कल्याणकारी खर्चे में वृद्धि का आधार असमानता में बढ़ोतरी है। अमीरी बढ़ने पर ही अमीर लोग ज्यादा टैक्स अदा करेंगे और तब ही सरकारी कल्याणकारी खर्चे में वृद्धि हो सकेगी।

उदाहरण के तौर पर मजदूर के वेतन में दस रुपये की वृद्धि तब ही होती है जब मालिक को दस लाख रुपये का लाभ हो। असमानता बढ़ने का दूसरा कारण यह है कि खुले बाजार की नीति में शेयर बाजार, प्रापर्टी तथा सोने में निवेश करने वाले विशेष तौर पर लाभान्वित हुए हैं। कपड़ा उद्योग और चमड़ा उद्योगों के निर्यातों से कुछ अर्धकुशल श्रमिकों के वेतन में वृद्धि अवश्य हुई है, परंतु शेयर बाजार से हुई आय की तुलना में यह तुच्छ है।

फरीदाबाद के निर्यात कारखानों में कार्यरत श्रमिक पिछले वर्ष चार हजार रुपये प्रतिमाह पाते थे तो इस वर्ष पांच हजार रुपये पाते हैं, परंतु प्रापर्टी में निवेश करने वाले को पिछले साल चार लाख का लाभ हुआ था तो इस साल दस लाख का। इसलिए आर्थिक विकास दर बढ़ने के साथ-साथ असमानता भी बढ़ रही है। असमानता में वृद्धि को वैश्वीकरण पर नहीं थोपना चाहिए। वैश्वीकरण के साथ-साथ बड़े औद्योगिक घरानों का वर्चस्व बढ़ना आर्थिक विकास की मौलिक प्रक्रिया है।

हल यह है कि अमीरों द्वारा अपनी संपत्ति के भद्दे प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए। धन कमाना अच्छा है, परंतु उसके भद्दे प्रदर्शन से अमीर और गरीब, दोनों की हानि होती है। अमीर यदि सामाजिक आक्रोश से बचना चाहता है तो उसे सादगी से जीना सीखना पड़ेगा अन्यथा आने वाले समय में उसकी अमीरी पर संकट पैदा होगा।

वे और बड़े होने लगते हैं, परंतु श्रम की आपूर्ति लगभग असीमित रहने से श्रमिक के वेतनमानों में कम ही वृद्धि होती है। जैसे मजदूर दो मंजिला मकान बनाए या 21 मंजिला, उसका वेतन समान रहता है, जबकि बिल्डर के लाभ में भारी वृद्धि होती है। अतः बढ़ती असमानता के लिए संप्रग सरकार को जिम्मेदार बताना गलत होगा। संप्रग सरकार की गलती मात्र इतनी है कि असमानता में वृद्धि की मौलिक प्रकृति पर लगाम कसने के लिए कारगर प्रयास नहीं किए गए हैं। वैश्वीकरण का एक और प्रभाव पड़ा है। सॉफ्टवेयर आदि क्षेत्रों में शिक्षित कर्मियों की मांग बढ़ी है और उनके वेतन भी बढ़े हैं।

आज सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र को 3-4 लाख रुपये का वार्षिक पैकेज मिलना आम बात हो गई है। यह सुखद उपलब्धि है। इससे निचले मध्यम वर्ग के तमाम लोगों को अच्छे वेतन मिले हैं, परंतु इससे असमानता की मूल समस्या का हल नहीं होता है।

वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार निजी संगठित क्षेत्र में कुल श्रमिकों की संख्या में प्रति वर्ष लगभग चार लाख की वृद्धि हो रही है। इसके सामने श्रम बाजार में प्रवेश करने वालों की संख्या में प्रति वर्ष लगभग 40 लाख की वृद्धि हो रही है। अतः जितने व्यक्तियों को उच्चकोटि के रोजगार मिल रहे हैं, गरीबों की संख्या में उससे दस गुना वृद्धि हो रही है। ये रोजगार असमानता की समस्या का समाधान नहीं हैं। तथापि भविष्य इसी प्रकार के रोजगारों का है। इनमें तीव्र वृद्धि की जरूरत है। ऐसा आम जनता को अच्छी शिक्षा पहुंचाने से ही संभव होगा। इसमें मुख्य बाधा स्वार्थी सरकारी तंत्र की सशक्त लॉबी है।

अंतिम आकलन इस प्रकार है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में असमानता का बढ़ना स्वाभाविक है। इस पर लगाम लगाने के प्रयास के प्रति सरकार उदासीन है। इससे समाज में विघटन बढ़ेगा। हल यह है कि अमीरों द्वारा अपनी संपत्ति के भद्दे प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए। धन कमाना अच्छा है, परंतु उसके भद्दे प्रदर्शन से अमीर और गरीब, दोनों की हानि होती है। अमीर यदि सामाजिक आक्रोश से बचना चाहता है तो उसे सादगी से जीना सीखना पड़ेगा अन्यथा आने वाले समय में उसकी अमीरी पर संकट पैदा होगा। ❑

खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश

भारत सरकार के बिजनेस पोर्टल की ही मान लें तो भारत भर में फैले करीब डेढ़ करोड़ खुदरा दुकानदार तो हैं हीं और उनके साथ करीब नौ करोड़ लोगों की जिंदगी भी जुड़ी है। इसके साथ ही अगर रेहड़ी–पटरी वालों को भी जोड़ दें तो यह संख्या अनुमान से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। जाहिर है उनकी रोजी–रोटी का जरिया खुदरा व्यापार ही है। उदारीकरण की शुरूआत के ठीक बीस साल बाद अगर रिटेल सेक्टर को 51 फीसदी विदेशी निवेश के लिए खोला जाएगा और इतनी बड़ी आबादी की रोजी–रोटी के सरोकारों को लेकर सवाल नहीं उठेंगे?

■ उमेश चतुर्वेदी

खुदरा व्यापार में भी विदेशी निवेश की मंजूरी देकर भारत सरकार ने एक बार फिर बहस को जन्म दे दिया है। खुदरा व्यापार को विदेशी निवेश के लिए खोलने के बाद बहस एक बार फिर वही है कि देशभर में फैले करीब डेढ़ करोड़ खुदरा दुकानदारों का क्या होगा। इतनी संख्या तो खुद भारत सरकार ही मानती है। लेकिन यह संख्या इससे और ज्यादा ही है। क्योंकि देशभर में रेहड़ी–पटरी वाले व्यापारियों का अभी तक कोई मुकम्मल आंकड़ा तैयार नहीं किया जा सका है।

लेकिन अगर भारत सरकार के बिजनेस पोर्टल की ही मान लें तो भारत भर में फैले करीब डेढ़ करोड़ खुदरा दुकानदार तो हैं हीं और उनके साथ करीब नौ करोड़ लोगों की जिंदगी भी जुड़ी है। इसके साथ ही अगर रेहड़ी–पटरी वालों को भी जोड़ दें तो यह संख्या अनुमान से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। जाहिर है उनकी रोजी–रोटी का जरिया खुदरा व्यापार ही है। उदारीकरण की शुरूआत के ठीक बीस साल बाद अगर रिटेल सेक्टर को 51 फीसदी विदेशी निवेश के लिए खोला जाएगा और इतनी बड़ी आबादी की रोजी–रोटी के सरोकारों को लेकर सवाल नहीं उठेंगे?

खुदरा क्षेत्र को विदेशी निवेश के बाद भारत में आने वाले बदलावों की चर्चा से पहले इससे जुड़े आंकड़ों पर विचार करना जरूरी है। रिटेल सेक्टर में विदेशी निवेशी को खोलने की मांग तो बरसों से हो रही है। इसकी वजह है भारत का विशाल मध्यवर्ग और तेजी से बढ़ती उसकी खरीद क्षमता। पिछले साल दुनिया की जानी–मानी रिसर्च कंपनी प्राइसवाटर हाउसकूपर ने भारत के रिटेल सेक्टर को लेकर एक

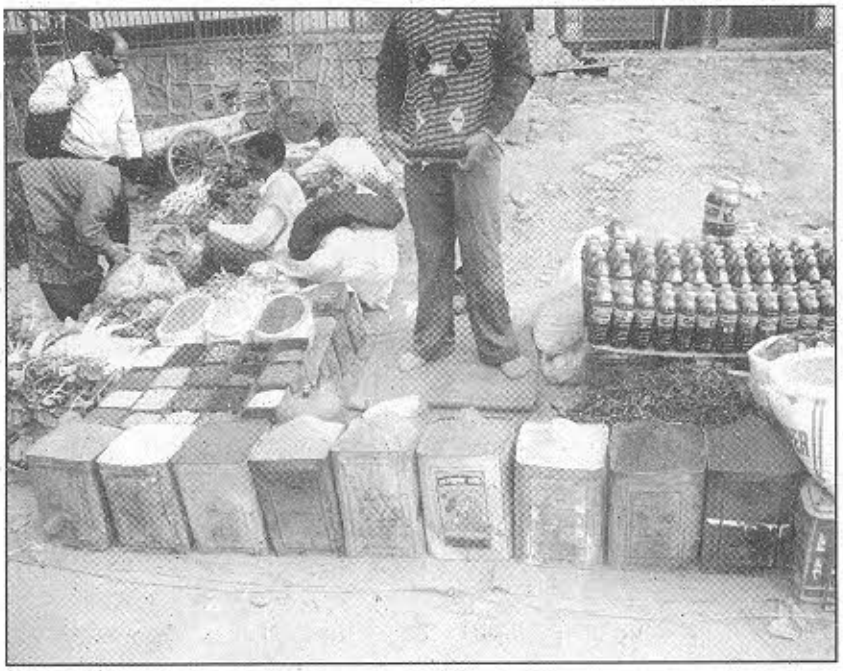

खुदरा व्यापार को विदेशी निवेश के लिए खोलने के बाद बहस एक बार फिर वही है कि देशभर में फैले करीब डेढ़ करोड़ खुदरा दुकानदारों का क्या होगा। इतनी संख्या तो खुद भारत सरकार ही मानती है। लेकिन यह संख्या इससे और ज्यादा ही है। क्योंकि देशभर में रेहड़ी–पटरी वाले व्यापारियों का अभी तक कोई मुकम्मल आंकड़ा तैयार नहीं किया जा सका है।

अध्ययन किया था। मजबूत और स्थिर 2011 शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में उसने अनुमान लगाया था कि भारत का खुदरा क्षेत्र 2014 तक बढ़कर 900 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी खुदरा कारोबार महज 500 अरब डॉलर का है। प्राइसवाटर हाउसकूपर ने अनुमान लगाया है कि 2010 से 2014 तक भारतीय रिटेल सेक्टर में औसतन चार फीसदी की सालाना वृद्धि होगी। प्राइसवाटर हाउस कूपर की यह रिपोर्ट मुख्यतः एशिया के खुदरा क्षेत्र पर केंद्रित है। इसके मुताबिक भारत का खुदरा क्षेत्र चीन और जापान के बाद तीसरे नंबर पर आता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक चीन में खुदरा क्षेत्र 2014 तक 4,500 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगा यानी चीन का खुदरा क्षेत्र भारतीय खुदरा क्षेत्र से पांच गुना ज्यादा होगा।

तीन साल पहले भारत सरकार ने भी देश के खुदरा बाजार पर अध्ययन कराया था। भारत सरकार के व्यापार पोर्टल के मुताबिक तब तक उपलब्ध अनुमानों के मुताबिक भारत का खुदरा बाजार 1,330,000 करोड़ रुपए का था। जिसमें खाद्य और किराना बाजार की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा यानी 7,92,000 करोड़ रुपए की

आंकी गई थी। यानी यह हिस्सेदारी भारत के कुल खुदरा बाजार में करीब 59.5 प्रतिशत बैठती है। इसके साथ ही कपड़े, वस्त्र उद्योग और फैशन संबंधी चीजों की खुदरा बाजार में हिस्सेदारी 9.9 प्रतिशत के साथ करीब 1,31,300 करोड़ रु. बैठती है। जो भारत के खुदरा बाजार में दूसरे स्थान पर है। हालांकि यह पूरा का पूरा ब्लॉक असंगठित है। आज संगठित किए जाने के नाम पर खुदरा बाजार को खोलने की जो हिमायत खुद सरकार कर रही है, उसका ही आंकड़ा बताता है कि भारत के खुदरा क्षेत्र का एक ब्लॉक ऐसा भी है, जो पहले से ही कहीं संगठित रहा है। इसमें टाइम वीयर की 48.9 प्रतिशत हिस्सेदारी और फुटवीयर (48.4 प्रशितत हिस्सेदारी है।

देश को उदारीकरण की तरफ ले जाने वाले प्रधानमंत्री और कांग्रेस के साथ ही भारतीय बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि खुदरा क्षेत्र को खोलने के बाद भारत के किसानों की हालत सुधरने वाली है। गुरुचरण दास जैसे लोगों का कहना है कि जिन देशों का खुदरा क्षेत्र संगठित क्षेत्र के हवाले कर दिया गया है, वहां के सुपर मार्केट आमतौर पर किसानों से सीधे अनाज और सब्जियां खरीदते हैं। फिर फ्रिज्ड करके उसे अपने सुपर मार्केटों

किसानों और उपभोक्ताओं को फायदा होने का तर्क देने वाले भूल जाते हैं कि देश में जिन करोड़ों लोगों की जीविका गली–मुहल्ले में रेहड़ी–पटरी लगाकर सब्जी–भाजी बेचकर चलती है, या गली के मुहाने की दुकान के सहारे रोजी–रोटी चल रही है, रिटेल चेन बढ़ने के बाद उनका क्या होगा। वैसे ही इस देश की आबादी का एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जिसके लिए नौकरियां पाना आसान नहीं है। रोजगार की हालत वैसे ही अभी तक खराब है। इस देश में बेरोजगारी जमकर है। भारत सरकार के ही आंकड़ों का हवाला दें तो भारत में इस समय बेरोजगारी दर 10.70 फीसदी है। जाहिर है कि जब खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश होगा तो इसमें बढ़ोत्तरी हो सकती है।

तक पहुंचाते हैं। और अपने रिटेल स्टोर के जरिए उपभोक्ताओं को बेचते हैं। यानी बिचौलिए की वहां भूमिका खत्म हो जाती है। चूंकि किसानों से खुदरा चेन वाली कंपनियां सीधे जिंस खरीदेंगी और उन्हें बेचेंगी तो किसानों को उनकी फसल की कहीं ज्यादा कीमत मिलेगी और उनके जरिए भारतीय उपभोक्ताओं को दस–बीस फीसदी कम कीमत पर बेचा जाएगा। यानी खुदरा क्षेत्र के संगठित होने से फायदा किसानों और उपभोक्ताओं–दोनों को होने की उम्मीद है। खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को खोलने का एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि भारत में अनाज और सब्जियों के रख–रखावा का उचित इंतजाम नहीं होने के चलते करीब 20 से 30 फीसदी तक अनाज और सब्जियां बरबाद हो जाती हैं।

खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश के बाद आने वाली कंपनियां भंडारण का उचित इंतजाम करेंगी और यह बरबादी रूकेगी। वैसे एक फायदा तो यह भी गिनाया जा रहा है कि खाद्यान्न की महंगाई दर में बढ़ोत्तरी के लिए वायदा कारोबार और उससे जुड़ी जमा खोरी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश के बाद वायदा कारोबारियों पर लगाम लगेगी। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वायदा कारोबारियों को मौका अधिकारियों की ढिलाई के बाद ही मिलती है। इसकी तरफ सरकारों ने अब तक मुकम्मल ध्यान नहीं दिया है।

विदेश में बड़े सुपरमार्केट आम तौर पर किसानों से सीधे खाद्यान्न खरीदते हैं, कोल्ड स्टोर में उनका भंडारण करते हैं, एयरकंडीशंड गाड़ियों में उनका परिचालन करते हैं और एयरकंडीशंड स्टोरों में उन्हें सीधे उपभोक्ताओं को बेचते हैं। यह कोल्ड चेन खुले स्थान में पड़े खाद्यान्न की बर्बादी को रोकती है। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20 से 30 प्रतिशत बर्बाद हो जाता है। आधुनिक रिटेल स्टोर के आने के बाद खाद्यान्न के दामों में 15–20 फीसदी कमी आने और किसानों की आय में 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। लेकिन हमें करीब डेढ़ दशक पहले की पंजाब की उस घटना को नहीं भूलना चाहिए। पंजाब सरकार ने एक विदेशी कंपनी से समझौते के बाद राज्य के किसानों को टमाटर बोने के लिए प्रोत्साहित किया था। तब कंपनी ने वादा किया था कि वह किसानों से उचित मूल्य पर टमाटर खरीदेगी और अपनी प्रोसेसिंग यूनिट में उससे केचप और दूसरी चीजें तैयार करेंगी। लेकिन जब टमाटर का बंपर उत्पादन होने लगा तो कंपनी तीस पैसे प्रति किलो की दर से टमाटर मांगने लगी। तब किसानों ने कंपनी को टमाटर बेचने की बजाय सड़कों पर ही फैला दिए थे। यानी किसानों को वाजिब हक कहां मिल पाया था।

किसानों और उपभोक्ताओं को फायदा होने का तर्क देने वाले भूल जाते हैं कि देश में जिन करोड़ों लोगों की जीविका गली–मुहल्ले में रेहड़ी–पटरी लगाकर सब्जी–भाजी बेचकर चलती है, या गली के मुहाने की दुकान के सहारे रोजी–रोटी चल रही है, रिटेल चेन बढ़ने के बाद उनका क्या होगा। वैसे ही इस देश की आबादी का एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जिसके लिए नौकरियां पाना आसान नहीं है। रोजगार की हालत वैसे ही अभी तक खराब है। इस देश में बेरोजगारी जमकर है। भारत सरकार के ही आंकड़ों का हवाला दें तो भारत में इस समय बेरोजगारी दर 10.70 फीसदी है।

जाहिर है कि जब खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश होगा तो इसमें बढ़ोत्तरी हो सकती है। क्योंकि जब घर के पास एयरकंडिशंड दुकानों में सस्ते सामान मिलेंगे तो रेहड़ी वालों को कौन पूछेगा, बगल के किराना स्टोर पर कौन जाएगा। यह सच है कि बिना विदेशी निवेश के ही रहेजा, टाटा, फ्यूचर, पीरामल, रिलायंस और भारती जैसे ग्रुपों ने रिटेल स्टोरों की शृंखला शुरू कर दी है। जाहिर है कि विदेशी निवेश के बाद इन पर भी दबाव बढ़ेगा। ❑

क्या हो विकास की सही परिभाषा

प्रायः कहते हैं कि यह गांव तो बहुत विकसित हो गया है। पर फसल काटने वाली इन मशीनों से कृषि मजदूरों का वही रोजगार छिन जाता है जिससे उनको ज्यादा उम्मीद होती है। फसल की कटाई करने को जो पैसा पहले गरीब मजदूरों को मिलता था वह अब अति धनी कंबाईन हारवेस्टर के मालिक को मिलता है। स्पष्ट है कि बाहरी तड़क–भड़क से, महंगी मशीनों या उपकरणों के आगमन से किसी गांव के विकास को नहीं आंका जा सकता है और न ही कुल आय बढ़ने के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गांव में अच्छा विकास हुआ है।

■ भारत डोगरा

सामान्य रूप से बाहरी चमक–दमक को देखकर कह दिया जाता है कि यह क्षेत्र विकास कर रहा है। मान लीजिए किसी महानगर में बहुत सी झुग्गी–झोपड़ियों बनी हैं और महानगर में कार्य करने वाले गरीब मजदूरों को इन सस्ते आवासों में आश्रय मिला हुआ है, क्योंकि इससे महंगी जगह में रहने के लिए पैसा उनके पास नहीं है। एक दिन उनकी झोपड़ियां तोड़ दी जाती हैं। इस स्थान पर एक आलीशान होटल बना दिया जाता है।

अब जो भी यहां से गुजरेगा, वह कहेगा कि यह इलाका तो बहुत विकसित हो गया। पर कोई उन मजदूरों से तो पूछकर देखे, जो पहले यहां रहते थे। उनमें से कई बेघर हो गए हैं और फुटपाथ पर सोते हैं। कई बच्चों का स्कूल छूट गया। अब जिन लोगों ने इसे विकास माना था, वह बहुत बुरा हुआ जो उन्हें उजाड़ा गया। पर कुछ अर्थशास्त्री बताते हैं कि अब देश की आय बढ़ गई है। झोपड़ियों के किराए व खरीद–बिक्री में एक वर्ष में तीन–चार लाख रुपये का कारोबार होता था।

अब एक दिन में ही इससे अधिक आय तो केवल होटल के कमरों के किराए से हो जाती है। इस तरह राष्ट्रीय आय में वृद्धि को प्रायः विकास की मुख्य पहचान माना जाता है पर जिन मजदूरों को उजड़ना पड़ा, उनके दुख–दर्द का आकलन इस परिभाषा में नहीं हो पाता है।

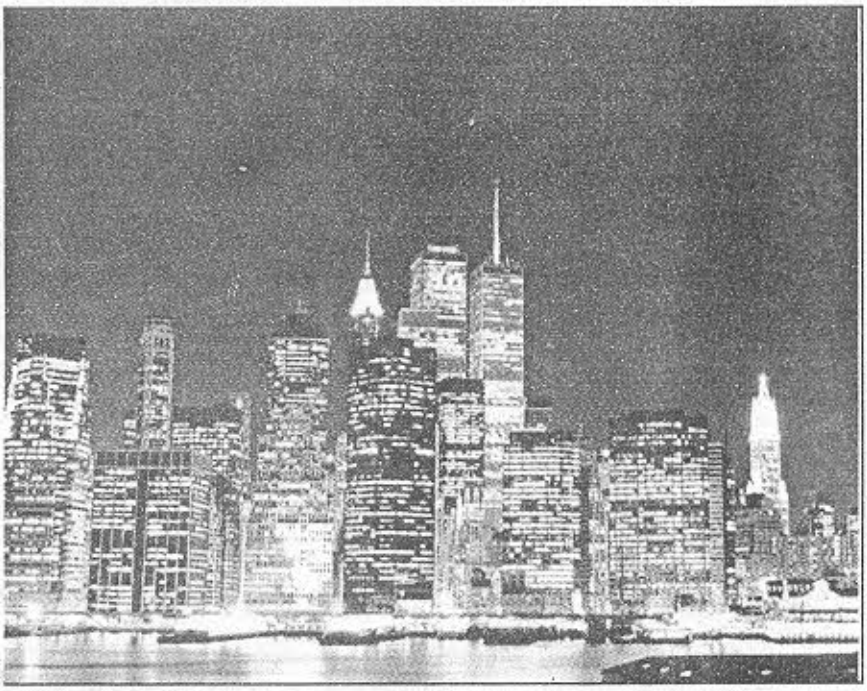

असमानता को दूर करना व समता को बढ़ाना जरूरी है। कुछ धनी देश गरीब देशों के संसाधन तरह–तरह से छीनते हैं या वहां की जमीन, खेती, खनिज, वन, श्रम आदि का अपने हित में उपयोग करने का दबाव बनाते हैं। इस कारण भी गरीब देशों के लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना कठिन होता है। व्यापार में यह देश अपने प्रभाव के बल पर लाभ का बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विषमता दूर करना व समता बढ़ाना जरूरी है।

राष्ट्रीय आय को कई तरह से नापा जाता है और इसका एक पैमाना जिसे अर्थशास्त्री ज्यादा उपयोग करते हैं उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। हाल के समय में कई विद्वानों ने इस मान्यता को चुनौती दी है कि जीडीपी से विकास की सही पहचान नहीं हो सकती है।

उदाहरण के लिए हम दो ऐसे गांवों की तुलना करें जो बाकी दृष्टियों में एक समान हैं पर केवल एक मामले में एक–दूसरे से भिन्न हैं कि एक गांव में कोई शराब नहीं पीता है और दूसरे गांव में शराब का खूब उत्पादन होता है। वहां शराब खूब बेची व खरीदी जाती है। इन गांवों को सिर्फ आय या जीडीपी की दृष्टि से देखा जाए तो शराब वाले गांव की नकद आय अधिक आंकी जाएगी, जबकि निश्चय ही दूसरे गांव का जीवन बेहतर है।

इसी तरह यदि आप ऐसे दो गांवों की तुलना करें जो अन्य सब मामलों में तो समान हैं, पर वृक्षों के संदर्भ में दोनों गांवों ने एक वर्ष में बहुत अलग नीतियां अपनाई। पहले गांव ने अपने सभी वृक्षों को बचाकर रखा जबकि दूसरे गांव ने अपने सभी वृक्षों को काटकर बेच दिया। निश्चय ही गांववासियों के भविष्य और पर्यावरण की रक्षा की दृष्टि से पहले गांव ने सही कार्य किया है, पर नकद आय का अल्पकालीन सृजन दूसरे गांव में बहुत अधिक हुआ, क्योंकि पेड़ों को काटने में मजदूरी दी गई और फिर पेड़ों की बिक्री से बहुत कमाई की गई।

मान लीजिए, किसी गांव में बड़े और धनी भूस्वामियों ने गरीब छोटे किसानों की जमीन किसी तरह हथिया ली और इस जमीन पर तमाम आधुनिक तौर–तरीकों का उपयोग कर बहुत थोड़े समय के लिए उत्पादन बढ़ा दिया। इस तरह गांव की

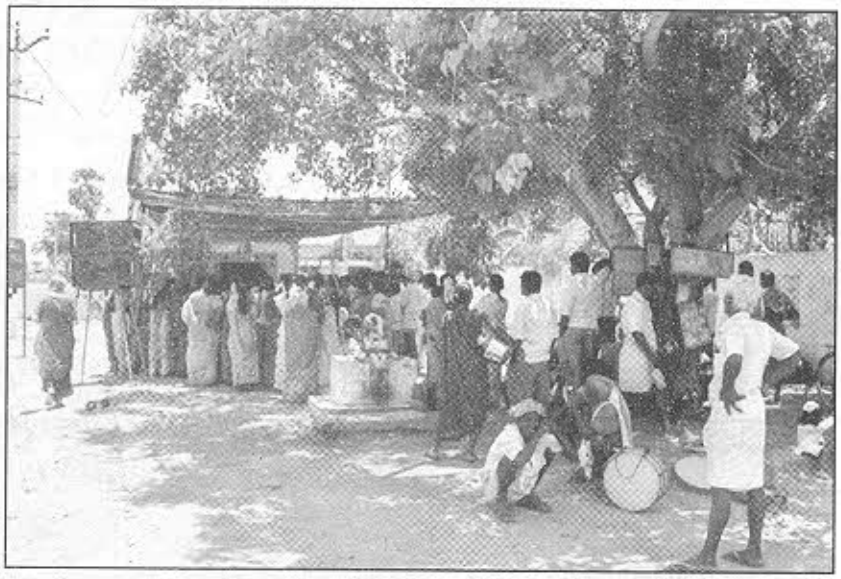

कुल नकद आय तो बढ़ी हुई नजर आएगी पर अधिकांश गरीब लोगों की हालत पहले से बदतर होगी। आधुनिक तकनीकें विशेषकर भारी–भरकम हारवेस्टर जैसी महंगी मशीनें जब किसी गांव में नजर आने लगती है तो लोग प्रायः कहते हैं कि यह गांव तो बहुत विकसित हो गया है। पर फसल काटने वाली इन मशीनों से कृषि मजदूरों का वही रोजगार छिन जाता है जिससे उनको ज्यादा उम्मीद होती है। फसल की कटाई करने को जो पैसा पहले गरीब मजदूरों को मिलता था वह अब अति धनी कंबाईन हारवेस्टर के मालिक को मिलता है।

स्पष्ट है कि बाहरी तड़क–भड़क से, महंगी मशीनों या उपकरणों के आगमन से किसी गांव के विकास को नहीं आंका जा सकता है और न ही कुल आय बढ़ने के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गांव में अच्छा विकास हुआ है। यदि किसी सुंदर घने जंगल को उजाड़कर कोई कंपनी वहां खनन करने लगे तो उस क्षेत्र में आय बहुत बढ़ी हुई नजर आएगी पर न तो यह भविष्य में मनुष्य के लिए अच्छा है न पशु–पक्षियों के लिए और न ही पर्यावरण के लिए। किसी गांव से किसानों को हटाकर उसे किसी बड़ी कंपनी को सौंप दो तो हो सकता है कि वह कंपनी उस क्षेत्र में किसानों से अधिक नकद आय का सृजन कर दे, पर ऐसा बदलाव किसानों को बर्बाद करेगा। यदि यह अधिक व्यापक स्तर पर हुआ तो खाद्य सुरक्षा व पर्यावरण पर भी संकट उपस्थित करेगा।

सवाल यह है कि यदि आय के आधार पर विकास का आकलन न करें तो

किसी गांव में बड़े और धनी भूस्वामियों ने गरीब छोटे किसानों की जमीन किसी तरह हथिया ली और इस जमीन पर तमाम आधुनिक तौर–तरीकों का उपयोग कर बहुत थोड़े समय के लिए उत्पादन बढ़ा दिया। इस तरह गांव की कुल नकद आय तो बढ़ी हुई नजर आएगी पर अधिकांश गरीब लोगों की हालत पहले से बदतर होगी। स्पष्ट है कि बाहरी तड़क–भड़क से, महंगी मशीनों या उपकरणों के आगमन से किसी गांव के विकास को नहीं आंका जा सकता है और न ही कुल आय बढ़ने के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गांव में अच्छा विकास हुआ है।

किस आधार पर करें? कई विद्वानों ने एक समाधान सुझाया है कि सब लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं कि नहीं, इसी आधार पर विकास का आकलन किया जाए।

सबकी बुनियादी जरूरतें पूरी होने का मतलब है कि सबको अच्छे स्वास्थ्य के लिए पेटभर पौष्टिक भोजन मिले और सबको आवास व वस्त्र उपलब्ध हों। सबको साफ पेयजल व स्वास्थ्य के लिए जरूरी शौचालय, स्नान घर, रसोई आदि उपलब्ध हो। जो विकास सब लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करे उसे अच्छा विकास माना जाए। पर इसके साथ कुछ अन्य सवाल भी खड़े होते हैं। आज के साथ हमें आने वाले कल के बारे में भी सोचना होगा। आज हम सबकी बुनियादी जरूरतें पूरी करें, इसके साथ यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आगे भी यह संभव हो। अतः हवा–पानी व पर्यावरण को बचाना, वनों की हरियाली की रक्षा, खनिजों को सजोकर रखना यह सब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर ही लोगों की जरूरतें भविष्य में पूरी हो सकेंगी।

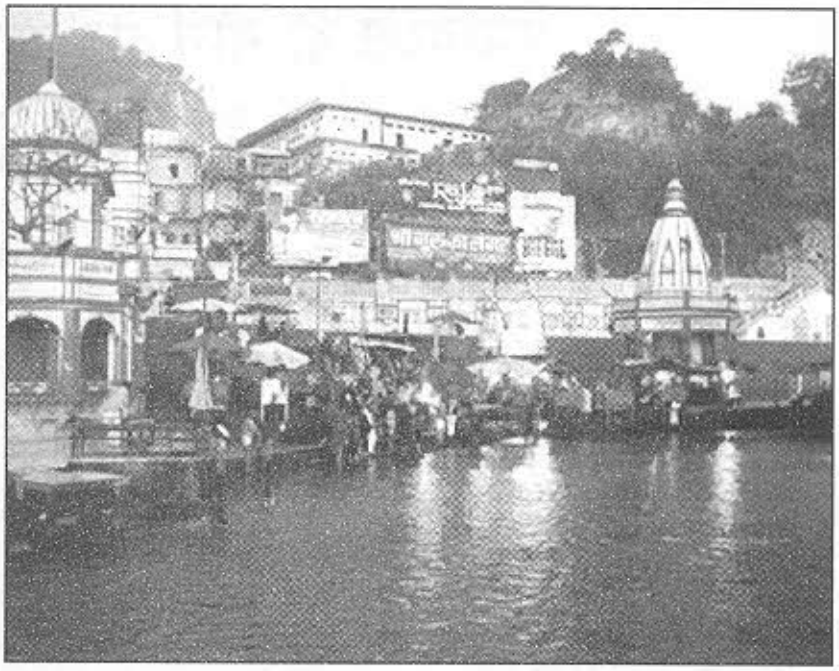

मान लीजिए किसी गांव ने एक नदी या झरने का पानी मोड़कर सभी गांववासियों की पानी की जरूरतों को पूरा कर लिया पर इसके कारण जंगल के पशु–पक्षियों को पानी नहीं मिला और वे मरने लगे तो क्या इसे उचित माना जाएगा? निश्चय ही नहीं। इसलिए मनुष्य को अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ सभी अन्य जीवों की जरूरतों और उनकी भलाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए पर्यावरण की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।

इसके साथ जुड़ा एक अन्य सवाल है कि यदि कुछ लोगों को बहुत अधिक भोग–विलास करने दिया गया व बहुत दौलत झपटने की अनुमति दी गई तो क्या सब लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा?

एक गांव के स्तर पर ही देख लीजिए कि यदि अधिकतर खेतों पर दो–तीन व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया तो क्या सब लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकेंगी? असमानता को दूर करना व समता को बढ़ाना जरूरी है। कुछ धनी देश गरीब देशों के संसाधन तरह–तरह से छीनते हैं या वहां की जमीन, खेती, खनिज, वन, श्रम आदि का अपने हित में उपयोग करने का दबाव बनाते हैं। इस कारण भी गरीब देशों के लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना कठिन होता है। व्यापार में यह देश अपने प्रभाव के बल पर लाभ का बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विषमता दूर करना व समता बढ़ाना जरूरी है।

कुछ ऊंचे पदों के लोग कह सकते हैं कि हमारा बुनियादी जरूरतों का उद्देश्य तो पूरा हो गया है इसलिए हमें भोग–विलास करने दिया जाए। पर यदि भोग–विलास बढ़ गया तो पर्यावरण नष्ट होगा और दूसरी कई सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, जो किसी भी हाल में ठीक नहीं होगा। ❑

आज के साथ हमें आने वाले कल के बारे में भी सोचना होगा। आज हम सबकी बुनियादी जरूरतें पूरी करें, इसके साथ यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आगे भी यह संभव हो। अतः हवा–पानी व पर्यावरण को बचाना, वनों की हरियाली की रक्षा, खनिजों को सजोकर रखना यह सब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर ही लोगों की जरूरतें भविष्य में पूरी हो सकेंगी।

पर्यावरण के मोर्चे पर शिकस्त

विकासशील देशों में शहरी विकास घोर अनियोजित तरीके से हुआ है। शहरों में वायु प्रदूषण के कारण करीब छह लाख लोग हर साल अकाल मौत का शिकार हो जाते हैं। इन शहरों में बड़ी मात्रा में वैश्विक संसाधन खप रहे हैं और ये कार्बन की भारी मात्रा वायुमंडल में उगल रहे हैं। शहरों में अधिकांश विश्व ऊर्जा की खपत हो रही है और हर साल करीब 6.5 अरब टन कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। आज विश्व में हर दस लोगों में से चार के पास शौचालय नहीं है और दस में से दो लोगों के पास पीने का स्वच्छ पानी नहीं है।

■ जगमोहन

जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने पर्यावरण की चुनौती से निपटने के लिए अनेक उपाय किए। आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये उपाय पर्याप्त सिद्ध हुए हैं और क्या हम पर्यावरण के मोर्चे पर जंग जीतने जा रहे हैं? इस संबंध में नौ प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

ये हैं गरीबी, विषमता और विभेदय शहरी स्थितियां जल एवं साफ–सफाईयां खाद्य सुरक्षा भूमि की उर्वराशक्ति में कमीयां, वन्य जैवविविधतायां, नदियां और अन्य जल संसाधन तथा ग्लोबल वार्मिंग। यद्यपि ये तमाम मदें किसी न किसी रूप में एक–दूसरे से जुड़ी हुई हैं, फिर भी इस मुद्दे को स्पष्ट तौर पर समझने के लिए यह जरूरी है कि इनका एक–एक करके विश्लेषण किया जाए। जहां तक गरीबी, विषमता और विभाजन का सवाल है, ये विश्व के अधिकांश भागों में पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। विकास के साथ–साथ वंचित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, विषमता बढ़ रही है और वर्ग विभाजन तीव्र हो रहे हैं।

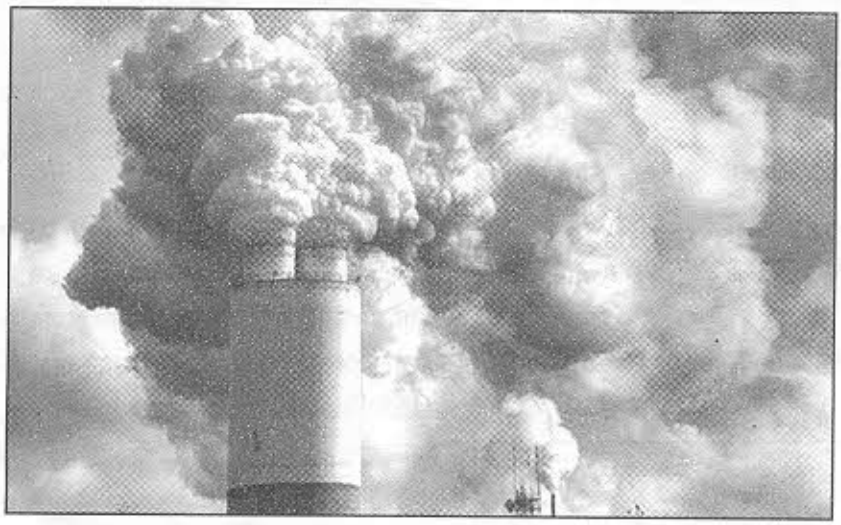

शक्तिशाली देशों का छोटा समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कब्जा जमाए बैठा है। इस समूह की आर्थिक विचारधारा के कारण धनी और धनी हो रहे हैं, शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं और विभिन्न देशों के बीच असमानता में वृद्धि हो रही है। इस्तानबुल में 9–13 मई को आयोजित सबसे कम विकसित देशों के चौथे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में खुलासा हुआ कि इस श्रेणी के देशों की संख्या 1971 में 25 से बढ़कर 2011 में 48 हो गई है। इन सब देशों की सम्मिलित जनसंख्या 88 करोड़ है और इन देशों में आधे से अधिक लोग 1.25 डॉलर रोजाना से भी कम पर गुजर–बसर करते हैं।

विकासशील देशों में शहरी विकास घोर अनियोजित तरीके से हुआ है। शहरों में वायु प्रदूषण के कारण करीब छह लाख लोग हर साल अकाल मौत का शिकार हो जाते हैं। इन शहरों में बड़ी मात्रा में वैश्विक संसाधन खप रहे हैं और ये कार्बन की भारी मात्रा वायुमंडल में उगल रहे हैं। शहरों में अधिकांश विश्व ऊर्जा की खपत हो रही है और हर साल करीब 6.5 अरब टन कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। आज विश्व में हर दस लोगों में से चार के पास

अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पर्यावरण को हुए नुकसान के प्रति चेत जाना चाहिए। उसे अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए और पर्यावरण को निगल रही नवउदारवाद की लालची शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहिए। साथ ही अपनी जीवन पद्धति में बदलाव लाकर प्रकृति पर पड़ रहे भारी बोझ को कम करना चाहिए। इससे प्रकृति के साथ तालमेल और संतुलन कायम होगा और पूरी मानवता एक परिवार के तौर पर एकजुट होगी।

शौचालय नहीं है और दस में से दो लोगों के पास पीने का स्वच्छ पानी नहीं है। इन दशाओं की स्वाभाविक परिणति जन स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति के रूप में सामने आती है। उदाहरण के लिए, भारत में हर साल करीब 3.8 करोड़ लोग पीलिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसे गंभीर जलजनित रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। करीब एक करोड़ लोग पानी में आर्सेनिक की अधिक मात्रा के कारण कैंसर के शिकार हैं। करीब 6.6 करोड़ लोग फ्लूरोसिस की गिरफ्त में हैं। इन रोगों का आर्थिक भार खौफनाक है। हर साल करीब 7.3 करोड़ कार्यदिवस और करीब 2400 करोड़ रुपये इन रोगों की भेंट चढ़ जाते हैं। एक तरफ वैश्विक आबादी हर साल करीब 8.7 करोड़ बढ़ जाती है, वहीं दूसरी तरफ खाद्यान्न की उपलब्धता साल दर साल कम हो रही है। पिछले तीन सालों के दौरान खाद्यान्न की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। इस कारण करीब 10 करोड़ लोगों पर गरीबी रेखा के नीचे जाने का खतरा मंडरा रहा है। विश्व की करीब 40 फीसदी कृषि योग्य जमीन की उर्वरा शक्ति घट रही है।

हरित क्रांति की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इससे न केवल कृषि उत्पादन लागत बढ़ी है, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भारी वस भी हुआ है। विश्व में हर साल करीब 70 लाख वर्ग हेक्टेयर भूमि से वन कम हो जाते हैं। वन में आगजनी भी गंभीर समस्या बन चुकी है। उदाहरण के लिए भारत में पांच प्रतिशत वन क्षेत्र आग से प्रभावित हो जाता है। विश्व की जैवविविधता पर भी तलवार लटक रही है। हर घंटे तीन प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। यदि विलुप्तता की यह दर कायम रही तो 2025 तक वैश्विक

एक तरफ वैश्विक आबादी हर साल करीब 8.7 करोड़ बढ़ जाती है, वहीं दूसरी तरफ खाद्यान्न की उपलब्धता साल दर साल कम हो रही है। पिछले तीन सालों के दौरान खाद्यान्न की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। इस कारण करीब 10 करोड़ लोगों पर गरीबी रेखा के नीचे जाने का खतरा मंडरा रहा है। विश्व की करीब 40 फीसदी कृषि योग्य जमीन की उर्वरा शक्ति घट रही है।

सकल घरेलू उत्पाद पर 7 प्रतिशत का नकारात्मक असर पड़ेगा। जैवविविधता की क्षति एक हरित मसला ही नहीं है। इसका खाद्यान्न, ईंधन, दवाओं के उत्पादन और भूमि उर्वरता पर सीधा असर पड़ता है। अगर इन मुद्दों की अनदेखी की जाएगी तो इसका सबसे अधिक नुकसान गरीब को ही उठाना पड़ेगा।

भूमि और अन्य संपत्ति के रूप में उनके पास जो भी साधन बचे हैं, उनकी उत्पादकता कम हो जाएगी। अनियोजित औद्योगीकरण और शहरीकरण से नदियां, झीलें, तालाब और अन्य जल संसाधन बुरी तरह प्रदूषित हो रहे हैं। वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारतीय सभ्यता की धुरी और अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा गंगा नदी मर रही है। 1970 से ग्लोबल वार्मिंग की गति तीन गुना बढ़ चुकी है। पिछला साल अब तक का सबसे गरम वर्ष था।

पिछले सौ सालों में सर्वाधिक गरम 12 साल में से 11 पिछले दो दशकों में रहे हैं। यह विरोधाभासी लग सकता है, किंतु सच है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बाढ़ और बारिश का प्रकोप बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर 1972 के बाद किए गए उपायों का कुछ सकारात्मक परिणाम भी आया है। पर्यावरण को लेकर जागरूकता में काफी वृद्धि हुई है और ओजोन छेद करीब–करीब बंद हो गया है। तेजाबी बारिश पर भी अंकुश लगा है, लेकिन पर्यावरण के प्रदूषित होने की गति के आलोक में इन लाभों का महत्व फीका पड़ जाता है। इससे भी बदतर यह है कि बेहद अन्यायपूर्ण, अनुचित और अनैतिक व्यवस्था सामने आ रही है। धनी लोगों का उपभोक्तावाद इस छोटे से ग्रह के सीमित संसाधनों पर असीमित भार डाल रहा है। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने में सबसे कम भूमिका गरीबों की होती है, लेकिन इसके दुष्परिणामों का सबसे अधिक खामियाजा इन्हें ही उठाना पड़ता है।

मार्च 2011 में जापान में भयंकर भूकंप के बाद आई सुनामी के बाद टोक्यो के गवर्नर इशिहारा ने भयाक्रांत होकर कहा था– यह हमारे उपभोक्तावाद का दैवीय दंड है। इशिहारा की इस तकलीफ को कोई भी कुटिल मुस्कान के साथ खारिज नहीं कर सकता। प्रकृति में दिव्यता के साथ–साथ संतुलन भी है और उपभोक्तावाद इस संतुलन को गड़बड़ा रहा है। यह समय है जब पिछले चार दशक के दौरान अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पर्यावरण को हुए नुकसान के प्रति चेत जाना चाहिए। उसे अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए और पर्यावरण को निगल रही नवउदारवाद की लालची शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहिए। साथ ही अपनी जीवन पद्धति में बदलाव लाकर प्रकृति पर पड़ रहे भारी बोझ को कम करना चाहिए। इससे प्रकृति के साथ तालमेल और संतुलन कायम होगा और पूरी मानवता एक परिवार के तौर पर एकजुट होगी। ❑

देश विरोधी आचरण

फई के अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भारतीय मानवाधिकारी, बुद्धिजीवी, पत्रकार और कश्मीरी अलगाववादी नेताओं का शामिल होना आईएसआई के भारत विरोधी मानसिकता को मिल रहे स्थानीय समर्थन को ही रेखांकित करता है। फई द्वारा आयोजित समारोह में शामिल हुए बुद्धिजीवी जाने–माने चेहरे हैं, जो मुसलमानों के मामले में तो मानवाधिकार, पंथनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की ढाल खड़ाकर कट्टरपंथियों के समर्थन में सड़कों पर उतर पड़ते हैं, किंतु जब पीड़ित हिंदू समुदाय का हो तो मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जाने कहां गायब हो जाती है?

■ बलबीर पुंज

आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो जिहादी एजेंडे से लैस पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई से पोषित कार्यक्रम के आधार पर भारत में बहुलतावादी समाज और मानवाधिकारों की रक्षा करने का दम भरते हैं? ये वही नाम हैं, जो राष्ट्रवादी संगठनों को सांप्रदायिक ठहराकर उनके कार्यक्रमों में भाग लेने से इंकार करते हैं, किंतु जिहादी संगठनों के मंच से मानवाधिकारों का परचम लहराने में देर नहीं लगाते।

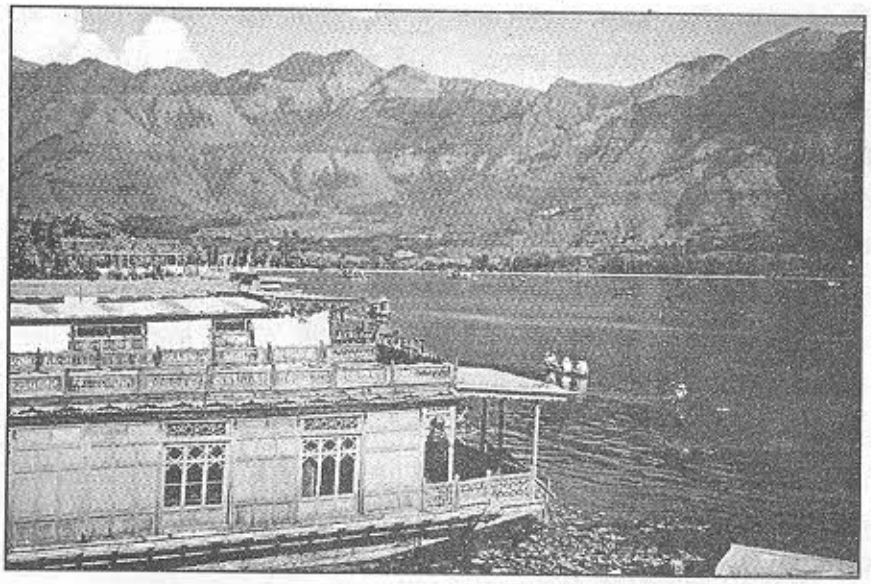

उक्त बैठक का एकमात्र लक्ष्य कश्मीर मुद्दे को भारत के हाथ से छीनना था। बैठक में मौजूद रिपब्लिकन पार्टी के डेन बर्टन कश्मीर मुद्दे को अमेरिकी संसद में उठाने के प्रबल समर्थक रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि भारत के इन बुद्धिजीवियों को फई के असली एजेंडे का ज्ञान नहीं था? हो सकता है कि उन्हें फई के वित्तपोषण के स्रोत की जानकारी नहीं हो, किंतु जिस विचार गोष्ठी में आप भाग लेने जा रहे हों, उसके विषय और उसके आयोजक की पृष्ठभूमि से कोई भला कैसे अनजान रह सकता है?

हाल में अमेरिका में कश्मीरी–अमेरिकी परिषद (कश्मीरी सेंटर) के कार्यकारी निदेशक गुलाम नबी फई को कश्मीर पर पाकिस्तान के एजेंडे के प्रचार के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों को चंदा देने और कई सम्मेलन आयोजित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एफबीआई के अनुसार फई की गतिविधियों के संचालन का खर्च आईएसआई वहन करती है। वह इसके राजनीतिक अभियान के लिए प्रति वर्ष 40 लाख डॉलर (18 करोड़ रुपये) देती है। कश्मीरी–अमेरिकन काउंसिल में फई जो भाषण देता था या उसके बैनर तले जो वक्तव्य जारी करता था उसका 80 प्रतिशत मसौदा भी आईएसआई तैयार करती थी।

फई के अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भारतीय मानवाधिकारी, बुद्धिजीवी, पत्रकार और कश्मीरी अलगाववादी नेताओं का शामिल होना आईएसआई के भारत विरोधी मानसिकता को मिल रहे स्थानीय समर्थन को ही रेखांकित करता है। फई द्वारा आयोजित समारोह में शामिल हुए बुद्धिजीवी जाने–माने चेहरे हैं, जो मुसलमानों के मामले में तो मानवाधिकार, पंथनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की ढाल खड़ाकर कट्टरपंथियों के समर्थन में सड़कों पर उतर पड़ते हैं, किंतु जब पीड़ित हिंदू समुदाय का हो तो मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जाने कहां गायब हो जाती है?

उक्त बैठक का एकमात्र लक्ष्य कश्मीर मुद्दे को भारत के हाथ से छीनना था। बैठक में मौजूद रिपब्लिकन पार्टी के डेन बर्टन कश्मीर मुद्दे को अमेरिकी संसद में उठाने के प्रबल समर्थक रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि भारत के इन बुद्धिजीवियों को फई के असली एजेंडे का ज्ञान नहीं था? हो सकता है कि उन्हें फई के वित्तपोषण के स्रोत की जानकारी नहीं हो, किंतु जिस विचार गोष्ठी में आप भाग लेने जा रहे हों, उसके विषय और उसके आयोजक की पृष्ठभूमि से कोई भला कैसे अनजान रह सकता है? आईएसआई की भारत विरोधी गतिविधियां जगजाहिर हैं। भारत को हजार घाव देने के एजेंडे के तहत वह आतंकवादी संगठनों सहित भारत में सक्रिय अलगाववादी समूहों का वित्तपोषण और उन्हें सैन्य सहायता उपलब्ध कराती रही है। यह आईएसआई का भूमि के ऊपर दिखने वाला चेहरा है, किंतु फई जैसे बुद्धिजीवी उसके भूमिगत चेहरे हैं, जो सभ्य समाज के शुभचिंतक होने का दंभ भरते हैं।

उपरोक्त सभी भारतीय प्रतिनिधि अपने–अपने क्षेत्र के सिद्धहस्त हैं और फई को यह भलीभांति ज्ञात था कि पाकिस्तानी एजेंडे के अनुरूप कश्मीर पर उनके वक्तव्य का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव होगा। इन बुद्धिजीवियों के रुख के कारण भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे पर मुंह चुराना पड़ रहा था और इसीलिए उसकी काट के लिए सरकार को विशेष तौर पर कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी वजाहत हबीबुल्ला को वाशिंगटन में कम्युनिटी अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में नियुक्त करना पड़ा था।

विडंबना यह है कि कल जो बुद्धिजीवी पाकिस्तानी एजेंडे का अंग थे, उनमें से कुछ आज संप्रग सरकार के अंग हैं। कश्मीर समस्या के निपटान के लिए सरकार द्वारा भेजे गए प्रमुख वार्ताकार ने फई के समारोह में शिरकत की। उनसे भारतीय हितों के अनुरूप समस्या के ईमानदार निवारण की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? विगत जनवरी माह में सरकार की ओर से कश्मीर भेजे गए उक्त प्रमुख वार्ताकार ने भाजपा को जम्मू–कश्मीर पर राजनीति बंद करने की सलाह दी थी। जम्मू–कश्मीर की समस्या घाटी के अलगाववादियों के कारण ही बेकाबू हुई है। शेष जम्मू–कश्मीर के लोग अमनपसंद और भारतीय सत्ता अधिष्ठान पर विश्वास रखने वाले हैं।

घाटी की मस्जिदों से भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, भारत की मौत की कामना की जाती है और पूरे प्रदेश में इस्लामी निजामत लाने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ने का जुनून पैदा किया जाता है। घाटी में तिरंगे को जलाकर पाकिस्तानी झंडा लहराया जाता है। कश्मीरी पंडित जम्मू–कश्मीर की संस्कृति के मूल वाहक थे। आज पूरी घाटी कश्मीरी पंडितों से खाली है। उनके मंदिर या तो बंद हैं या ध्वस्त कर दिए गए। उनके रिहायशी मकानों पर जिहादियों का कब्जा है। जम्मू–कश्मीर की समस्या पाकिस्तान प्रायोजित अलगाववादियों की देन है। जम्मू–कश्मीर की समस्या पर विचार करते हुए इन घटनाक्रमों से क्या आंखें मूंद ली जाएं?

सरकार की ओर से नियुक्त उक्त प्रमुख वार्ताकार वस्तुतः जिस मानसिकता से ग्रस्त हैं वह पाकिस्तानी एजेंडे का ही विस्तार है। पाकिस्तान कश्मीर मसले पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की बात लंबे समय से उठाता रहा है। कुछ समय पूर्व पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों को स्वशासन का अधिकार देने का कुटिल प्रस्ताव रखा था। इसके लिए उसने संयुक्त राष्ट्र से मध्यस्थता की अपील की थी। संयुक्त राष्ट्र के अधीन सरकार के गठन का अर्थ होगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रस्तावों को स्वीकार कर रहा है।

राष्ट्र संघ के मध्यस्थ होने के नाते ओवन डिक्सन ने 1950 में जनमत संग्रह कराने की बात की थी और सुझाव दिया था कि जो जिस हिस्से में जीते, उसे वह भाग दे दिया जाए। भारत इस पर सहमत था, किंतु पाकिस्तान के दबाव पर बाद में संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में केवल घाटी में जनमत संग्रह कराने पर जोर देने के कारण भारत ने डिक्सन के संशोधित प्रस्ताव को नकार दिया था। पाकिस्तान लंबे समय से अपने उसी एजेंडे को साकार करने में लगा है।

फई द्वारा आयोजित वैचारिक गोष्ठियों में भारतीय बुद्धिजीवियों की भागीदारी से देश में प्रचलित सेक्युलर पाखंड का ही खुलासा होता है। यह विकृति समाज के हर क्षेत्र में व्याप्त है। जम्मू–कश्मीर के अलगाववादियों के सुर में सुर मिलाते हुए कुछ बुद्धिजीवी दिल्ली की धरती पर सत्ता अधिष्ठान को चुनौती देते हैं। सरकार मौन रहती है। संसद पर हमला करने वाले अफजल की फांसी की सजा केवल इसीलिए लंबित रखी गई है, क्योंकि इससे मुस्लिम समाज के कट्टरपंथियों के बिदक जाने का खतरा है। कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण और इस्लामी जिहाद के कड़वे सच को ढकने के लिए सेक्युलर खेमा भगवा आतंक का हौवा खड़ा करता है। ऐसे शुभचिंतकों के रहते यदि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में कामयाब हो रहा हो तो आश्चर्य कैसा? ❑

समस्या

सीआईए और मोसाद एजेंसियों के खतरनाक खेल

दुनिया की दो प्रमुख खुफिया एजेंसियों–सीआईए और मोसाद ने मिलकर भारत को तबाह करने की घातक रणनीति बनाई है। वे आतंकवादियों की तरह आत्मघाती हमले तो नहीं करेंगी, लेकिन जो करेंगी, उसका असर बम के धमाकों से भी ज्यादा खतरनाक होगा। उनके निशाने पर आम लोगों की जान नहीं, पूरी व्यवस्था होगी। उनकी साजिश व्यवस्था के प्रति लोगों को विश्वास तोड़ने की है।

■ ब्रजमोहन जैन

खबर यह भी आ रही है कि इस साजिश में देश की खुफिया एजेंसी के कई अधिकारी भी शामिल हैं। मोसाद और सीआईए के ऐसे घिनौने ऑपरेशन से दो बातें एकसाथ होंगी। पहला तो देश की जनता का विश्वास टूटेगा, दूसरा यह कि इनका शिकार बने नेता या अधिकारी फिर समाज के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा।

आज हमारे देश के ऊपर एक गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जिन पर इस खतरे से निपटने की जिम्मेदारी है वे हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। एक तरह से उनका साथ दे रहे हैं। हमारे सरकारी तंत्र को भी इस खतरे के बारे में पता है लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ है। दुनिया की दो प्रमुख खुफिया एजेंसियों–सीआईए और मोसाद ने मिलकर भारत को तबाह करने की घातक रणनीति बनाई है। वे आतंकवादियों की तरह आत्मघाती हमले तो नहीं करेंगी, लेकिन जो करेंगी, उसका असर बम के धमाकों से भी ज्यादा खतरनाक होगा। उनके निशाने पर आम लोगों की जान नहीं, पूरी व्यवस्था होगी। उनकी साजिश व्यवस्था के प्रति लोगों को विश्वास तोड़ने की है। सीआईए और मोसाद मिलकर एक ऐसे खतरनाक आपरेशन को अंजाम देने जा रही है, जिससे देश के सरकारी तंत्र और इस तंत्र को चलाने वाले लोगों पर से जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा। इस साजिश को अंजाम देने के लिए दोनों खुफिया एजेंसियों ने देश के राजनेताओं, न्यायाधीशों, अधिकारियों, उद्योगपतियों और पत्रकारों को निशाने पर लिया है। लोगों का देश पर विश्वास मजबूत करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग हैं। सीआईए और मोसाद ने वैसे लोगों को अपने निशाने पर ले रखा है जो भारत में सांप्रदायिकता एकता के पक्षधर हैं और अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं। वे हिंदू हैं, मुसलमान हैं और ईसाई भी हैं। वे भारत की गंगा–जमुना संस्कृति के वाहक हैं।

सीआईए और मोसाद मिलकर एक ऐसे खतरनाक आपरेशन को अंजाम देने जा रही है, जिससे देश के सरकारी तंत्र और इस तंत्र को चलाने वाले लोगों पर से जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा। इस साजिश को अंजाम देने के लिए दोनों खुफिया एजेंसियों ने देश के 35 राजनेताओं, न्यायाधीशों, अधिकारियों, उद्योगपतियों और पत्रकारों को निशाने पर लिया है।

दाहिने हाथ से काम करो और बाए को भनक तक न लगे, यह खुफिया एजेंसियों के काम करने का मूलमंत्र होता है। खुफिया एजेंसियां अपने कामों को बड़ी सफाई से अंजाम देती हैं। जो इन एजेंसियों के लिए काम करते हैं, उन्हें इस बात की भनक नहीं होती कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए और इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनियाभर में फैली हैं। अपने दुश्मनों से निपटने के लिए उनके पास न सिर्फ पैसे हैं बल्कि वे अत्याधुनिक तकनीक से भी लैस हैं। आंखों के सामने सबूत होता है लेकिन उन पर यकीन नहीं होता है। अमेरिका और इजरायल की खुफिया एजेंसियां इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में सबसे अव्वल हैं। इनके मंसूबे खतरनाक हैं। भारत के ही लोगों का इस्तेमाल करके दोनों खुफिया एजेंसियों ने देश के नामचीन लोगों को बेआबरू करने की पूरी तैयारी कर ली है।

सीआईए और मोसाद की योजना यह है इन 35 लोगों को एक–एक करके निशाने पर लिया जाए और उनके चरित्र, उनकी मर्यादा एवं उनकी साख को नेस्तनाबूत कर दिया जाए। इसके तहत इन लोगों की आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाना,

इनके ऊपर गबन का आरोप लगवानाया इनके एकाउंट में भारी–भरकम धनराशि जमा कर देना और टेक्नॉलाजी की मदद से इनका नकली एमएमएस बनाकर न्यूज चैनलों में बंटवाने से लेकर अन्य तमाम तरह की योजनाएं हैं, जिससे एक झटके में कोई शख्स समाज की नजरों में गिर जाए और उसे सफाई देने का भी मौका न मिले। इसके लिए मोसाद और सीआईए देश के एक न्यूज चैनल, कई पत्रकारों एवं अधिकारियों को इस्तेमाल करेगी।

भारत को खोखला करने के इस ऑपरेशन में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए 20 मिलियन डॉलर खर्च करने जा रही है। हजारों लोगों को इस काम के लिए नियुक्त किया गया है। सीआईए के 90 एजेंट इस पूरे अभियान को दिशा और गति दे रहे हैं। इन एजेंसियों ने जिन लोगों को अपने निशाने पर लिया है, उनके फोन और इंटरनेट पर होने वाले सभी संपर्क और संवाद का रिकॉर्ड सीधे सीआईए मुख्यालय में दर्ज हो रहा है। वक्त–वेवक्त इन जानकारियों का इस्तेमाल देश में बवंडर खड़ा करने के लिए हो सकता है।

लोगों को बदनाम करने का जिम्मा कई देशी–विदेशी कंपनियों को दिया गया है, जिसका काम है नए–नए साफ्टवेयर बनाकर इंटरनेट पर जासूसी करना। सीआईए और मोसाद की योजना साफ है कि वे भारत को भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और उन अफ्रीकी देशों की तरह बना देना चाहती हैं, जहां की जनता का विश्वास नेताओं से उठ चुका है। जैसे वहां के नेताओं, न्यायाधीशों, अधिकारियों और पत्रकारों की साख खत्म हो गई है, वैसा ही हमारे देश में होने वाला है।

इनकी योजना और तैयारी इतनी खतरनाक है कि इनके एजेंट्स लोगों के शयनकक्षों तक में घुसकर अपना जाल बिछा लेंगे और किसी को कानोंकान खबर भी नहीं होगी। लोगों की गतिविधियां, टेलीफोन पर बातचीत, दोस्तों और दूसरे लोगों के साथ उनका मिलना–जुलना, यानी हर बात की जानकारी इन एजेंसियों को रहती है।

सबसे अफसोसनाक बात यह है कि भारत की गुप्तचर एजेंसियों को इन खुफिया एजेंसियों के ऑपरेशन के बारे में पूरी खबर है कि आने वाले दिनों में सीआईए और मोसाद देश के नामचीन लोगों का चरित्र हनन करने वाली है। फिर भी उन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। देश की खुफिया एजेंसियों ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। इस साजिश में देश की खुफिया एजेंसी के कई अधिकारी इतने बेबस हैं कि वे षड्यंत्र के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने उनके हाथ बांध दिए हैं। वे सिर्फ देश के खिलाफ होने वाले इस षड्यंत्र को देखकर आंसू बहा सकते हैं। मोसाद और सीआईए के ऐसे घिनौने आपरेशन से दो बातें एक साथ रहेंगी।

पहला तो यह कि देश की जनता का विश्वास टूटेगा, दूसरा यह कि इनका शिकार बना नेता या अधिकारी फिर समाज के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। जब जनता के विश्वास के केंद्र टूटेंगे तो देश कमजोर होगा, अराजकता फैलेगी और इसका फायदा उठाकर अलगाववादी शक्तियां अपने कारनामों को अंजाम दे सकेंगी। विघटनकारी तत्व देश की अखंडता पर हावी हो जाएंगे। सांप्रदायिकता को हवा दी जाएगी और यह भारत की संप्रभुता को छिन्न–भिन्न कर देगी।

आजादी के बाद भारत एक हुआ, मजबूत बना। विकास की गतिविधियों और भाई चारे की ताकत से भारत विश्वशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। आजादी के बाद अमेरिका और यूरोप के कई राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भविष्यवाणी की थी कि भारत कुछ ही सालों में टूटकर बिखर जाएगा, देश के अंतहीन दंगे और हर तरफ अलग देश की मांग करने वाले अलगाववादी आंदोलन होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। आज देश की जनता ने वैसी ताकतों को सिरे से नकार दिया है जो देश को धर्म के नाम पर, आरक्षण के नाम, मुसलमानों के नाम पर और जाति के नाम पर घृणा फैलाने का काम करती हैं। हिंदू–मुसलमान एक साथ एक इस देश की प्रगति के हिस्सेदार होंगे, यही बात सीआईए और मोसाद को खटक रही है। भारत में अमन अमरीका और इजरायल को गंवारा नहीं है। नए भारत की जनता का धर्मनिरपेक्ष विश्वास अब इतना मजबूत हो चुका है कि उसने मुंबई जैसे हमले के बावजूद देश में एक भी जगह दंगे नहीं होने दिए। सांप्रदायिक संगठनों को इसका जरा भी फायदा नहीं उठाने दिया। जो लोग इस श्रेय के हकदार है, उन्हें सीआईए और मोसाद ने अपने निशाने पर ले लिया है।

सीआईए और मोसाद भारत में चरित्र हनन का एक खतरनाक खेल, खेल रही है। ऐसे में देश की सरकार और मीडिया को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर टेलीविजन चैनलों को विशेष सतर्क रहना पड़ेगा, जो आपसी प्रतियोगिता की वजह से खबरों को बिना छानबीन किए दिखा देते हैं। वे खुफिया एजेंसियों की साजिश का माध्यम बन सकते हैं। देश की जनता से भी यही उम्मीद है कि वह इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से पहले पूरी सावधानी बरतेगी। ❑

आतंकियों को अभयदान क्यों?

मुंबई पर बार–बार होने वाले हमले पूरे देश को चेताते हैं कि हमें एक कारगर खुफिया, निरोधात्मक और दंडात्मक व्यवस्था तैयार करनी होगी। इसके तहत देश में कहीं भी किसी के भी खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी करनी होगी। अगर कोई आतंक के माध्यम से भारत पर हमला करने की जुर्रत करता है तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। अमेरिका में 9/11 हमले के बाद कोई भी उसके खिलाफ आतंकी हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया। मुंबई को भी इसी भावना के साथ चलना होगा कि इस पर यह अंतिम हमला है।

■ अरुण जेटली

मुंबई में हालिया बम धमाके हमें स्मरण दिलाते हैं कि हम आतंकी निशाने पर सबसे ऊपर हैं। हम इस दलील पर संतुष्ट नहीं हो सकते और अपनी तैयारियों को ढीला नहीं छोड़ सकते कि मुंबई पर 31 माह बाद आतंकी हमला हुआ है। बार–बार मुंबई पर ही क्यों आतंकी हमले किए जाते हैं?

कारण स्पष्ट है। मुंबई पर हमले भारतीय अर्थव्यवस्था पर आघात हैं। इसकी दुनिया भर में चर्चा होती है। मुंबई पर बड़े आतंकी हमलों का सिलसिला 1993 से शुरू हुए। ट्रेन धमाके और 26/11 के आतंकी हमलों के बाद यह सिलसिला अब तक जारी है। मुंबई शहर की मूलभावना उद्यमिता है। यह समावेशी है और लचीली भी। किंतु इसका यह मतलब नहीं कि आतंक के विरुद्ध मुंबई का रवैया नरम है। मुंबई एक हमले के बाद दूसरे हमले का इंतजार नहीं कर सकती।

मुंबई पर बार–बार होने वाले हमले पूरे देश को चेताते हैं कि हमें एक कारगर खुफिया, निरोधात्मक और दंडात्मक व्यवस्था तैयार करनी होगी। इसके तहत देश में कहीं भी किसी के भी खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी करनी होगी। अगर कोई आतंक के माध्यम से भारत पर हमला करने की जुर्रत करता है तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। अमेरिका में 9/11 हमले के बाद कोई भी उसके खिलाफ आतंकी हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया। मुंबई को भी इसी भावना के साथ चलना होगा कि इस पर यह अंतिम हमला है।

भारत उपद्रवी पड़ोसियों से घिरा है। यद्यपि हालिया हमले से संबंधित तथ्यों की पड़ताल जारी है और ऐसे में यही उचित है कि कोई भी अभी अंतिम निष्कर्ष तक

मुंबई की भावना को बार–बार होने वाले आतंकी हमलों से जख्मी नहीं किया जा सकता। जो लोग पाकिस्तान के साथ वार्ताओं के पक्षधर हैं, उन्हें स्मरण होना चाहिए कि आज पाकिस्तान में हालात बेकाबू हैं और वहां अराजकता फैली है। दिखावे के रूप में वहां आतंक के खिलाफ युद्ध चल रहा है। किंतु पाकिस्तान के उन लोगों से गहरे संबंध हैं जो आतंकवाद फैलाते हैं!

न पहुंचे। फिर भी इसमें कोई शक नहीं है कि सीमा पार के प्रोत्साहन पर ही लश्करे–तैयबा और इस जैसे अनेक आतंकी संगठन खड़े किए गए हैं। इनका लक्ष्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थिरता फैलाना है। कसाब और शिकागो मामले से मिले साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं। पश्चिमी सीमा पर हमारे पड़ोसी ने आतंकवाद को राष्ट्र नीति के औजार के तौर पर इस्तेमाल किया है।

पाकिस्तानी से जुड़े सूत्रों के बिना विश्व में कहीं भी कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है। पाकिस्तान को उचित ही वैश्विक आतंक की धुरी बताया जाता है। विश्व के सर्वाधिक कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को विश्व में अगर कहीं पनाह मिली तो केवल पाकिस्तान में। इंडियन मुजाहिद्दीन का गठन इसलिए किया गया ताकि घरेलू आतंकियों को संगठित किया जा सके। हालिया वर्षों में भारत पर हुए अनेक आतंकी हमलों के सूत्र इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़े हैं। बड़ी संख्या में इसके सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण यह पिछले कुछ वर्षो से शांत पड़ा था।

लगता है अब ये फिर से संगठित हो रहे हैं। आतंकी घटनाओं के सिलसिले के प्रति भारत की प्रतिक्रिया क्या है? जाहिर है, हम इनकी भर्त्सना की रस्मअदायगी करते हैं। हम हादसों के शिकार लोगों की मौत पर विलाप करते हैं और घायलों को राहत प्रदान करते हैं। किंतु इस सबसे भारतीय समाज को क्या संकेत मिलता है, खासतौर पर उन लोगों के संबंध में जो सरकार में हैं और आतंकवाद के खिलाफ समर्पण कर रहे हैं। आतंकी घटनाओं की पड़ताल और आतंकियों को दंडित करने के लिए राजीव गांधी ने टाडा लागू किया

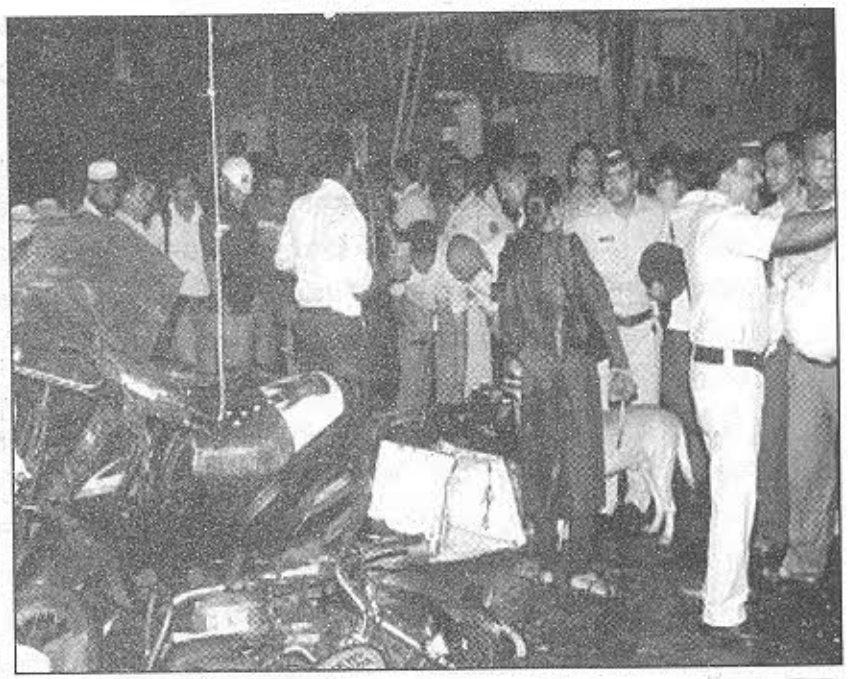

था। कुछ राज्यो ने किसानो के खिलाफ इसका दुरुपयोग किया किंतु इसे रद्द नहीं किया गया।

जब 1993 के विस्फोट करने वाले आतंकियों के खिलाफ इसका सही इस्तेमाल किया जा रहा था, तो इसे रद्द करने का एक अभियान छेड़ दिया गया और टाडा को रद्द कर दिया गया। इसके बाद पोटा को इस आधार पर रद्द किया गया कि हमें आतंक के खिलाफ विशेष कानून की आवश्यकता नहीं है।

जो लोग आतंक के खिलाफ विशेष कानून लाने का आवश्यकता नहीं समझते, वे अब सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए एक बेहद पक्षपाती कानून लाने की सोच रहे हैं, जिसके तहत केवल एक समुदाय को ही दंडित किया जा सकेगा। जब आतंकवादी बटला हाउस में शरण पाते हैं तो कुछ वरिष्ठ राजनेता हमारे सुरक्षा बलों पर सवाल खड़े करते हैं जो बटला हाउस मुठभेड़ में शामिल थे।

जब तक पाकिस्तान कट्टरता को त्यागने, पारदर्शिता लाने, लोकतंत्र के पथ पर चलने और एक राष्ट्र के तौर पर खुद को आतंक से अलग करने का संकल्प नहीं लेता, इसके साथ किसी भी प्रकार के संबंध संदेहास्पद होंगे। पाकिस्तान के संबंध में सरकारी और गैरसरकारी तत्वों के बीच की विभाजन रेखा मिट चुकी है।

वोट बैंक की राजनीति के चलते कुछ राजनेता आजमगढ़ में संदिग्धों के घर जाकर उनसे सहानुभूति प्रकट करने को मजबूर हो जाते हैं। एक कांग्रेसी राजनेता तो आतंक के शिकार लोगों के परिजनों से मिलने के बजाए आरोपी के परिजनों से मिलने पहुंच जाते हैं।

संसद हमले के दोषी की फांसी की सजा टालने के पीछे भी वोट बैंक और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ही जिम्मेदार है। सितंबर 2003 तक जिस नेशनल काउंटर टेररिज़्म सेंटर के गठन का वादा किया गया था, उसे अब तक पूरा नहीं किया गया।

मुख्यधारा के कुछ राजनीतिक दलों ने आतंकियों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आप आतंकी हमले करके साफ बच सकते हैं। इन हालात में हम सुनिश्चित नहीं हो सकते कि मुंबई पर फिर आतंकी हमले नहीं होंगे। माओवादी विद्रोह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। जब गृहमंत्री ने इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने की कोशिश की तो उन्हीं की पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार को वैकल्पिक कदम उठाने चाहिए। जब माओवादी भारत के लोकतंत्र पर हमला करते हैं तो उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने के बजाए आपको लचर दलीलें सुनने को मिलती हैं कि लोग माओवादी क्यों बनते हैं। क्या सिविल समाज के अलंबरदारों या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के एजेंडे में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा रहा है?

मुंबई की भावना एक राष्ट्रीय हल की दिशा में कदम बढ़ाने की मांग करती है, ताकि तमाम राजनीतिक, प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी बाधाओं को दूर करते हुए आतंक का खात्मा किया जा सके। मुंबई की भावना को बार–बार होने वाले आतंकी हमलों से जख्मी नहीं किया जा सकता। जो लोग पाकिस्तान के साथ वार्ताओं के पक्षधर हैं, उन्हें स्मरण होना चाहिए कि आज पाकिस्तान में हालात बेकाबू हैं और वहां अराजकता फैली है। दिखावे के रूप में वहां आतंक के खिलाफ युद्ध चल रहा है। किंतु पाकिस्तान के उन लोगों से गहरे संबंध हैं जो आतंकवाद फैलाते हैं।

जब तक पाकिस्तान कट्टरता को त्यागने, पारदर्शिता लाने, लोकतंत्र के पथ पर चलने और एक राष्ट्र के तौर पर खुद को आतंक से अलग करने का संकल्प नहीं लेता, इसके साथ किसी भी प्रकार के संबंध संदेहास्पद होंगे। पाकिस्तान के संबंध में सरकारी और गैरसरकारी तत्वों के बीच की विभाजन रेखा मिट चुकी है। भारत की विदेश नीति को जनवरी 2004 के उस संयुक्त बयान पर लौटना होगा कि वार्ता इस शर्त पर हो सकती है कि पाकिस्तान के भूभाग को भारत के खिलाफ आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ❑

सदस्यता संबंधी सूचना

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि "स्वदेशी पत्रिका" के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है।

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	100/–	1000/–
अंग्रेजी	100/–	1000/–

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

पता : **स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22**

आतंकवाद से त्रस्त चीन

चीन को अब शंघाई सहयोग परिषद में आतंकवाद के विरुद्ध अपनी आवाज पहले से भी अधिक बुलंद करनी होगी। पाकिस्तानी सरकार को पटरी पर लाने में भारत आज तक सफल नहीं हो पाया है लेकिन चीन ने अगर कड़ा रवैया अपना लिया तो पाक सरकार मजबूर हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान चीन का सबसे घनिष्ठ मित्र है और अब वह चीन पर ही पूरी तरह निर्भर होने वाला है। ओसामा कांड ने अमेरिकियों की आंखें खोल दी हैं। पता नहीं, उइगर आतंकवाद चीन की आंखें कब खोलेगा?

■ वेदप्रताप वैदिक

अपने यहां कहावत है कि 'जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई'! चीन अब तक भारत की शिकायतों पर आंख मूंदे बैठा रहता था। उसे पाकिस्तान की आतंकवादी भूमिका कभी आपत्तिजनक नहीं दिखाई पड़ती थी। वह जान बूझकर मक्खी निगल रहा था लेकिन अब काशगर में हुए भयंकर रक्तपात ने उसे झकझोर दिया है। चीन की सरकार के प्रवक्ता ने अब दो–टूक शब्दों में आरोप लगाया है कि चीन के शिंच्यांग (सिनक्यांग) प्रांत के उइगर मुसलमानों को पाकिस्तान भड़का रहा है। पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में उन्हें आतंकवादी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। काशगर में पकड़े गए उइगर आतंकवादियों ने, जो चीनी नागरिक हैं, यह सत्य उगला है कि उन्होंने बम वगैरह बनाना पाकिस्तान में ही सीखा है।

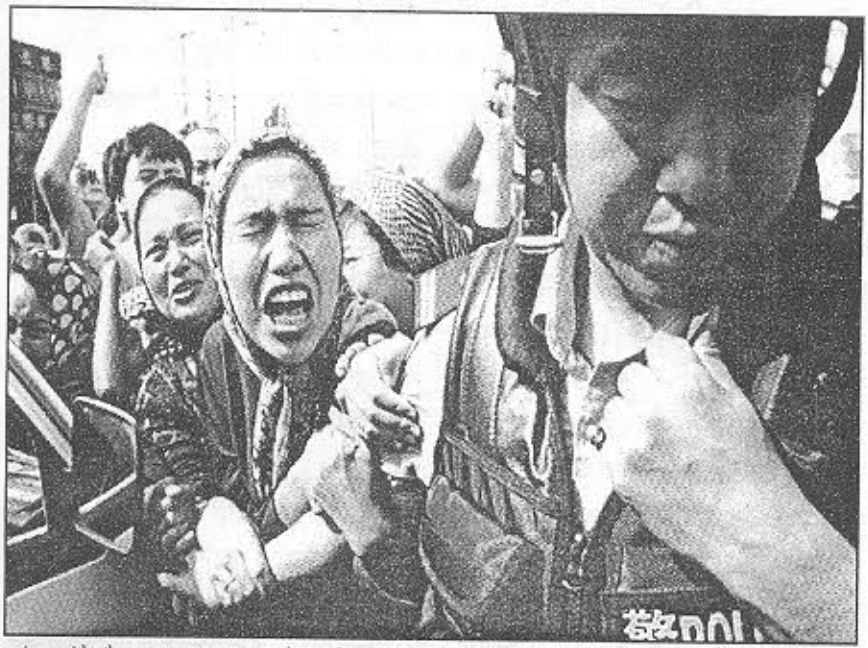

आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान की सरकार चीनियों को वही तर्क देती है, जो भारत सरकार को देती है यानी आतंकवादी 'गैर–राज्यीय तत्व' हैं। उन्हें राज्य की कोई मदद नहीं है। इस तर्क को भारत की सरकार तो मान लेती है, उस पर अमेरिकी दबाव भी बना रहता है लेकिन चीनी रवैया काफी आक्रामक है। इस मामले में पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी को फोन करके चीनी नेताओं को अपनी सफाई देनी पड़ी थी. . .

सबसे पहले तो यह जाना जाए कि शिंच्यांग क्षेत्र कहां है, ये उइगर लोग कौन हैं और चीन व पाकिस्तान से उनका क्या संबंध है। शिंच्यांग चीन का पश्चिमी प्रांत है, जिसकी सीमा भारत, पाकिस्तान, किरगिजिस्तान, उजबेकिस्तान और मंगोलिया आदि देशों को स्पर्श करती है। पाकिस्तान ने चीन को अवैध रूप से 'आजाद कश्मीर' की कुछ जमीन दे रखी है। अगर वह नहीं दी गयी होती तो चीन के इस प्रांत की सीमा भारत से भी काफी दूर तक जुड़ती। लगभग 16 लाख वर्ग किमी में फैला यह प्रांत पूरे चीन का एक बटे छह भू–भाग है और इसमें लगभग दो करोड़ लोग रहते हैं। इसमें 47 अलग–अलग जातियों के लोगों की आबादी है, जिनमें उइगर लोगों का प्रतिशत 45 यानी सबसे ज्यादा है। लेकिन पिछले 60 सालों में चीन की साम्यवादी सरकार ने कुछ ऐसी चाल चली कि उइगर लोग अपने ही घर में अल्पसंख्यक हो गए। वहां गैर–उइगरों की संख्या 55 प्रतिशत हो गई।

चीन की मुख्य जाति–हान लोगों को वहां इतनी बड़ी संख्या में बसा दिया गया है कि वे ही अब शिंच्यांग के असली मालिक बन गए हैं। आज स्थानीय सरकार और प्रशासन में उइगरों का प्रतिनिधित्व नाममात्र का है। सभी प्रमुख

स्थानों पर हान लोग जमे हुए हैं। वे चीनी भाषा बोलते है जबकि उइगरों की भाषा तुर्की है। उनका चेहरा–मोहरा, खान–पान, रहन–सहन, सभ्यता–संस्कृति उइगरों से बिल्कुल अलग है। उरूमची, काशगर, खोतान जैसे बड़े–बड़े शहरों में चीनियों का बोलबाला साफ दिखाई पड़ता है। बड़े–बड़े मकान, बड़ी– बड़ी कारें, बड़ी–बड़ी दुकानें सब चीनियों के पास हैं और गंदी बस्तियां, छोटी–मोटी नौकरियां और वंचनापूर्ण जीवन उइगरों के खाते में है।

शिंच्यांग को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने में बीजिंग की सरकार ने क्या–क्या कदम नहीं उठाए लेकिन संपूर्ण प्रगति का लाभ लोगों में बराबर नहीं बंट सका। मक्खन तो चीनी हान लोग लूट ले गए और उइगरों को छाछ भी नहीं मिली। घनघोर असंतोष का मुख्य कारण यही है। उइगर असंतोष को भड़काने में आर्थिक विषमता की मुख्य भूमिका तो है ही, वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, जिसके कारण शिंच्यांग को 'स्वतंत्र तुर्किस्तान' बनाने की मांग समय– समय पर उठती रही है।

शिंच्यांग, तिब्बत, मंगोलिया और मंचूरिया–ये कुछ ऐसे देश हैं, जो चीन की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर अवस्थित हैं। इन राष्ट्रों या प्रदेशों पर चीन ने कई बार कब्जा कर लिया और कई बार ये उसके हाथ से फिसल गए। 1933 और 1944 में शिंच्यांग चीन के हाथ से निकलकर 'पूर्वी तुर्किस्तान का इस्लामी गणराज्य' बन गया था। उसे सोवियत संघ का समर्थन भी था। लेकिन माओ की लाल सेना ने डंडे के जोर पर उसे दुबारा अपने साथ मिला लिया गया। अब अनेक उइगर लोग वहां पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामी आंदोलन चला रहे हैं। आजादी के इस आंदोलन को अमेरिका और पाकिस्तान में बसे अनेक प्रबुद्ध और मालदार उइगर डटकर समर्थन दे रहे हैं।

पहले च्यांग काई शेक और फिर साम्यवादी सरकारों ने शिंच्यांग में इतना भयंकर दमन–चक्र चलाया हुआ था कि उइगर उग्रवादी ज्यादा सिर नहीं उठा पाते थे लेकिन जब से पाकिस्तान इस्लामी आतंकवाद का गढ़ बना है, उइगर आतंकवाद भी बलवान हो उठा है। उइगर आतंकवादियों को पाकिस्तान के साथ सांठ–गांठ बढ़ाने में तीन कारणों से विशेष लाभ होता है। एक तो पाकिस्तान के 'आजाद कश्मीर' से शिंच्यांग एकदम साथ लगा हुआ इलाका है। दोनों के बीच अच्छी खासी सड़क है, जिस पर मोटर और ट्रक दौड़ते हैं। अच्छे मौसम में लोग पैदल या घोड़ों–गधों पर भी आर–पार आते–जाते रहते हैं। इस्लामाबाद और उरूमची (शिंच्यांग की राजधानी) के बीच सीधी हवाई जहाज सेवा भी बहुत ही रियायती दरों पर प्रतिदिन उपलब्ध है। शिंच्यांग के शहरों में बने मेडिकल कॉलेजों में आप सैकड़ों पाकिस्तानी छात्रों को देख सकते हैं।

दूसरा कारण यह है कि उइगर लोग मुसलमान हैं। पाकिस्तान के लोग उनके प्रति विशेष भाईचारा महसूस करते हैं। तीसरा कारण, उइगर लोग देखने में चीनियों से एकदम अलग लगते हैं। वे पाकिस्तान के उत्तरी हिस्सों के वाशिंदों की तरह लगते हैं। लगभग तीन हजार उइगर शिंच्यांग से भागकर पाकिस्तान में बस गए हैं। चीनी सरकार इन उइगरों पर कड़ी नजर रखने के लिए पाकिस्तान सरकार पर हमेशा दबाव बनाए रखती है। पाकिस्तान से पकड़कर कई उइगरों को अमेरिका ने ग्वांटेनामोबे में भी बंद कर दिया था।

आतंकवाद के मसले पर पाकिस्त की सरकार चीनियों को वही तर्क देती जो भारत सरकार को देती है या आतंकवादी 'गैर–राज्यीय तत्व' हैं। उ राज्य की कोई मदद नहीं है। इस त को भारत की सरकार तो मान लेती उस पर अमेरिकी दबाव भी बना रहता लेकिन चीनी रवैया काफी आक्रामक है इस मामले में पिछले दिनों आसिफ अल जरदारी को फोन करके चीनी नेताओं क अपनी सफाई देनी पड़ी थी और आजकल आईएसआई के मुखिया शुजा पाश बीजिंग में हैं।

उइगर आतंकवादियों और आम जनता ने दो साल पहले शिंच्यांग में इतना दंगा मचाया था कि दो सौ लोग मारे गए थे। उसके बाद छोटे–मोटे कई दंगे हुए। चीन के अन्य हिस्सों में बसे उइगरों ने भी अपनी आवाज बुलंद की थी।

अगर इन लोगों ने चीन के बड़े शहरों में बम रखने शुरू कर दिए और इनके साथ तिब्बती और मंगोल जातियां भी मिल गईं तो चीन को पता चलेगा कि भारत के दर्द का अर्थ क्या है। चीन को अब शंघाई सहयोग परिषद में आतंकवाद के विरुद्ध अपनी आवाज पहले से भी अधिक बुलंद करनी होगी। पाकिस्तानी सरकार को पटरी पर लाने में भारत आज तक सफल नहीं हो पाया है लेकिन चीन ने अगर कड़ा रवैया अपना लिया तो पाक सरकार मजबूर हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान चीन का सबसे घनिष्ठ मित्र है और अब वह चीन पर ही पूरी तरह निर्भर होने वाला है। ओसामा कांड ने अमेरिकियों की आंखें खोल दी हैं। पता नहीं, उइगर आतंकवाद चीन की आंखें कब खोलेगा? ❑

भारतीय नारी पर पश्चिमी प्रभाव

वर्तमान समाज में नैतिकता के मापदण्ड बेहद लचीले हो गए है। नारी में भी नैतिकता का भारतीय परंपरागत भाव तिरोहित हो रहा है। समय और स्थान के अनुरूप हर प्रकार की मान्यताओं में शीर्षासन होता रहा है। लेकिन प्रदर्शन/विज्ञापन ही होड़ में वर्तमान नारी स्वयं ही चीरहरण में लगी हुई है। सात्विक रूचि और कलात्मकता, उदारीकरण की बयार में वह बह गई है।

■ रेणु पुराणिक

पश्चिमी सभ्यता के संक्रमण के कारण जहां नारी जीवन में विविध बदलाव आए हैं, वहां यौन सुचिता भी संक्रमित हुई है। यर्थाथ के नाम पर नग्नता को अपनाया जा रहा है। टी.वी. चैनलों पर धारावाहिको का जो प्रसारण किया जा रहा है, उसका सत्य धीरे–धीरे पूर्ण समाज का सत्य बनता जा रहा है। षड्यंत्रकारी भूमिका में नारी का चित्रांकन दूरदर्शन के पर्दे से वास्तविक जीवन में अपने पाँव पसार चुका है।

निःसंदेह आज नारी को समानाधिकार प्राप्त है लेकिन फिर भी वह दहेज के लिए ईंधन की भांति जलाई जाती है। कदम–कदम पर तिरस्कृत/बहिस्कृत होती है। वर्तमान समय सभ्यता का युग माना जाता है लेकिन सभ्यता का युग तो तब आएगा जब नारी की मर्जी के बिना उसका नाम भी किसी व्यक्ति के होंठो पर नहीं आएगा।

विज्ञापनों में नारी देह का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। नारी का दैहिक प्रदर्शन उसकी स्वतंत्रता का सूचक नहीं है। विज्ञापित नारी अकेली उत्तरदायी नहीं है। यदि सूक्ष्म अध्ययन किया जावे तो वर्तमान समय में भी समाज में नारी का स्थान कुछ–कुछ वैसा ही है जैसा किसी दुकान, मकान, आभूषण अथवा चल–अचल संपत्ति का हो।

वर्तमान समाज को अपनी सामंती सोच एवं संकीर्ण मानसिकता, सड़ी गली व्यवस्था, रूढ़िगत कुप्रथा को नारी उत्कर्ष हेतु तिलांजलि देनी ही होगी। पुरूष वर्ग को ऐसा वातावरण तैयार करना होगा, जिससे नारी को एक जीवंत–मानुषी, जन्मदात्री एवं राष्ट्र की सृजनाहार समझा जाए न कि मात्र भोग्या?

वर्तमान समय में सामाजिक संदर्भ में नारी की चर्चा करते समय यह पंक्तियां सटीक लगती है :–

"राम भले ही पैदा हो या
ना हो मेरी नगरी में,
पर रावण तो पहले भी था
और आज भी है।"

प्राचीन समय से लेकर आज तक समग्र कालखण्ड को नारी संदर्भ में खंगाला जाए तो समय की सीप में जहां–तहां बहुमूल्य मोती मिलेंगे, परंतु वही पर अनगिनत समस्या भी। आधुनिकता के आक्टोपसी संजाल में फंसी नारी की विभिन्न मुद्राओं एवं चीखों को भी देखा व सुना जा सकता है। भूमंडलीकरण के दौर में नारी की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं आया है। लेकिन फिर भी ग्लैमर, फैशन, स्वतंत्रता और आसमान छूने की चाह तो तीव्रगति से बढ़ती जा रही है।

भूमंण्डलीकरण नारी के लिए ऐसी चक्की है जिसमें उन्हें पीसा जा रहा है। इसमें एक चेहरा बेबस गरीब नारी का है जिसकी आंखों में उसके भूखे बच्चे के प्रति वेदना समाई है तो उसका दूसरा चेहरा उस लड़की का है जिसका मुँह क्रोध से तमतमाया हुआ है। भूमंडलीकरण के दौर में नारी स्थिति में अपेक्षित पूर्ण सुधार आना संभव नहीं लगता है। नारी का छद्म रूप दिखाकर उन असंख्य नारियों की वेदना नहीं छिपाई जा सकती है जो गांवों में रहती है। नारियों का वास्तविक स्वरूप वही है जो गांवों में अभावों से जूझती और रूढ़ियों में जकड़ी हुई दिखाई देती हैं।

वर्तमान समाज में नैतिकता के मापदण्ड बेहद लचीले हो गए है। नारी में भी नैतिकता का भारतीय परंपरागत भाव तिरोहित हो रहा है। समय और स्थान के अनुरूप हर प्रकार की मान्यताओं में शीर्षासन होता रहा हैं। लेकिन प्रदर्शन/विज्ञापन की होड़ में वर्तमान नारी स्वयं ही चीरहरण में लगी हुई है। सात्विक रूचि और कलात्मकता, उदारीकरण की बयार में वह बह गई है। प्रेम और स्नेह के साथ अपनत्व तिरोहित होता जा रहा है। अतएव नारी को स्वयं की रक्षा हेतु जाग्रत रहना अति आवश्यक है। ❑

प्रतिभाएं बनाएंगी आर्थिक महाशक्ति

हम चाहते हैं कि भारतीय प्रतिभाएं देश की मिट्टी को सोना बना दें और देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बना दें तो हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। यद्यपि देश में नौकरियों के अवसर बढ़ रहे हैं लेकिन हमें देश के रोजगार बाजार में उभरकर सामने आ रही सचाईयों पर भी ध्यान देना होगा। अब भी देश में कुछ ही प्रतिभाशाली युवाओं की मुठ्ठी में चमकीले रोजगार हैं और अधिकांश के हाथ रोजगार रहित हैं।

■ जयंतीलाल भंडारी

हाल में प्रकाशित भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा वर्ष 2010 के अनुसार अमेरिका, चीन, जापान और रूस के बाद भारत दुनिया का पांचवां सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। उल्लेखनीय है कि अनेक सर्वेक्षणों के अनुसार भारत अपनी नई पीढ़ी की बदौलत पूरी दुनिया में अग्रणी आर्थिक व कारोबारी भूमिका दर्ज कराते हुए 2020 में विकसित देश होगा और 2050 में अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा।

वस्तुतः नई प्रतिभाओं की बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था में समृद्धि देने वाली कई नई प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। भारत निवेश एवं विनिर्माण के एक आकर्षक गंतव्य स्थल के रूप में परिणित हो गया है। रोनाल्ड बर्जर स्ट्रैटिजी कंसल्टेंट्स नाम की विश्व प्रसिद्ध संस्था ने अपने सव्रेक्षण में पाया है कि अटलांटिक महासागर के दोनों ओर स्थित कंपनियों के लिए भारत खुली चुनौती पेश कर रहा है। अब दुनिया भर की कंपनियों के एजेंडे में भारत की साख बढ़ी है।

स्थिति यह है कि भारतीय कंपनियों के बगैर विश्व उद्योग की तरक्की की कल्पना अधूरी हो गई है। आज बहुराष्ट्रीय औद्योगिक कंपनियों के एजेंडे में भारत पहली प्राथमिकता के रूप में शामिल है। पिछले दिनों बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा

उल्लेखनीय है कि अनेक सर्वेक्षणों के अनुसार भारत अपनी नई पीढ़ी की बदौलत पूरी दुनिया में अग्रणी आर्थिक व कारोबारी भूमिका दर्ज कराते हुए 2020 में विकसित देश होगा और 2050 में अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। वस्तुतः नई प्रतिभाओं की बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था में समृद्धि देने वाली कई नई प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं।

दुनिया के देशों में उद्यमी और प्रतिभा तराशने तथा नया बिजनेस शुरू करने के लिए बेहतरीन माहौल की स्थिति पर कराए गए एक सर्वे में यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि भारतीय मिट्टी में नए उद्यमियों की पौध सबसे ज्यादा लहलहा रही है तथा भविष्य में भी विश्व स्तर पर भारतीय प्रतिभाओं के आगे बढ़ने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। निश्चित रूप से प्रतिभाओं की बुनियाद पर खड़ा भारत का बाजार दुनिया का सबसे अधिक संभावनाओं वाला बाजार है। कोई दो–ढाई दशक पहले तक भारत के जिस बाजार को दीन–हीन समझा जाता था, आज वह बेहद चमकीला हो गया है।

यह साफ तौर पर अनुभव किया जा रहा है कि जीवन शैली और उपभोग की आदतों के परिप्रेक्ष्य में भारतीयों की इच्छाओं में भारी बदलाव आया है। भारत का मध्यम वर्ग भारतीय बाजार की

बुनियाद है। वस्तुतः कई क्षेत्रों में भारतीय बाजार नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। भारत सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में बहुत आगे है। इसके अलावा देश ने वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, खनन, निर्माण क्षेत्र, थोक व खुदरा क्षेत्र में भी भारी प्रगति की है। इन विभिन्न क्षेत्रों की ताकत के कारण दुनिया के बड़े–बड़े राष्ट्र प्रमुख, उद्योगपति और निवेशक लाभ की आशा में भारतीय बाजार की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

अब भारत न केवल दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ बाजार है बल्कि अमेरिका जैसे विकसित देश भी भारतीय कारोबार के आगे बढ़ने से लाभान्वित हो रहे हैं। पिछले एक वर्ष में दुनिया की पांच महाशक्तियों–अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस सहित कई प्रमुख विकासशील देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने कारोबार के मकसद से भारत की यात्राएं की हैं। भारत और दुनिया के विभिन्न देशों के नए कारोबारी समझौते एक–दूसरे की आवश्यकता के रूप में उभरकर सामने आए हैं।

यदि हम चाहते हैं कि भारतीय प्रतिभाएं देश की मिट्टी को सोना बना दें और देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बना दें तो हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। यद्यपि देश में नौकरियों के अवसर बढ़ रहे हैं लेकिन हमें देश के रोजगार बाजार में उभरकर सामने आ रही सचाईयों पर भी ध्यान देना होगा। अब भी देश में कुछ ही प्रतिभाशाली युवाओं की मुठ्ठी में चमकीले रोजगार हैं और अधिकांश के हाथ रोजगार रहित हैं। चूंकि देश की 50 फीसद आबादी 15 से 35 वर्ष वाले युवाओं की है और इसके अलावा आने वाले 20 वर्षों में यहां युवाओं की तादाद में करीब 24 करोड़ का इजाफा होगा, लेकिन इस विशाल युवा आबादी के शिक्षित–प्रशिक्षित होने की चुनौती हर दम सामने खड़ी होगी। कम शिक्षित युवाओं को रोजगार की व्यवस्था कठिन होगी।

इस समय पांच युवा पुरुषों में सिर्फ दो और तीन युवा लड़कियों में से सिर्फ एक दसवीं तक पढ़ पाते हैं। इसके अलावा देश के पांच करोड़ से अधिक

युवक–युवतियां ऐसे हैं, जिन्होंने जीवन में कभी स्कूल नहीं देखा है। यूनीसेफ की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ज्यादातर युवा रोजगार बाजार में जगह नहीं तलाश पाने के कारण तनाव, निराशा और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा प्रतिवर्ष 2.5 फीसद आबादी रोजगार की लाइन में बढ़ती जा रही है।

देश में 2007 में बेरोजगारी की दर जहां 7.3 थी, वहीं 2010 में बढ़कर 9.4 तक पहुंच गई। नेशनल नॉलेज कमीशन को अब तक ऐसा तरीका नहीं मिला, जो कम शिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाकर भारत की तस्वीर बदल दे। ऐसे में सरकार के द्वारा सभी के लिए रोजगार के प्रयास जरूरी हैं। कम योग्य युवाओं के लिए हमें प्रशिक्षण एवं सेवा क्षेत्र में अवसर खोजने होंगे और उन्हें रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों से शिक्षित–प्रशिक्षित करना होगा। गांवों में काफी संख्या में जो गरीब, अशिक्षित और अर्धशिक्षित लोग हैं, उन्हें अर्थपूर्ण रोजगार देने के लिए कौशल प्रशिक्षण से सुसज्जित करके निम्न तकनीक विनिर्माण में लगाना होगा।

यूनीसेफ की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ज्यादातर युवा रोजगार बाजार में जगह नहीं तलाश पाने के कारण तनाव, निराशा और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा प्रतिवर्ष 2.5 फीसद आबादी रोजगार की लाइन में बढ़ती जा रही है। देश में 2007 में बेरोजगारी की दर जहां 7.3 थी, वहीं 2010 में बढ़कर 9.4 तक पहुंच गई।

एक ओर देश के करोड़ों विद्यार्थियों को मानव संसाधन में बदलने के लिए शिक्षा संस्थाओं की नई भूमिका आवश्यक होगी, वहीं दूसरी ओर देश की नई पीढ़ी को नए आर्थिक दौर में अधिक उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धा की दौड़ में कार्य करने के लिए पहल क्षमता और उत्साह के साथ कार्य करना होगा। ऐसी ऊर्जावान एवं प्रतिभाशाली नई पीढ़ी से ही देश आर्थिक महाशक्ति बनेगा। ❑

राजस्थान प्रांत का विचार वर्ग : अन्य प्रांतों के लिए प्रेरणा

कई ग्रामों में ऐसे बदमाश पैदा हो गए है जो जबरदस्ती लोगो की जमीन पर कब्जा करके छोटा–मोटा मुआवजा देकर लोगों को चलता करते है, लोग डर के मारे कुछ बोलते नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है की राष्ट्रीय स्तर पर ये काम केंद्रीय सरकार कर रही है और प्रदेश स्तर पर प्रदेश सरकारे। – कश्मीरी लाल

30–31 जुलाई 2011 को राजस्थान के एक ऐतिहासिक एवं सुंदर नगर जोधपुर में स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा प्रांत का विचार वर्ग सम्पन्न हुआ। उद्घाटन सत्र में प्रसिद्ध समाजसेवी श्री दमदार लाल बंग का अध्यक्षीय भाषण हुआ। विचार वर्ग के मुख्यवक्ता श्री कश्मीरी लाल जी रहे। विचार वर्ग में नए अमरीकी आर्थिक संकट, खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का नया पंगा, भू–अधिग्रहण,नदियों, विशेषकर गंगा माता का संकट, कृषि क्षेत्र में बी.टी. से लेकर मौनसेंटो के नए षड़यंत्र और चीन की चुनातियों जैसे विषयों के बारे में चर्चा की गई।

दूसरा सत्र में श्री अश्विनी महाजन ने खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के विषय पर विस्तार से हर पक्ष लिया। सरकार ने विदेशी निवेश के नाम पर रोजगार में वृद्धि का छलावा किया गया है और दूसरा की इससे कीमते कम होंगी, ऐसा तर्क दिया जा रहा है। उन्होंने उन गार्डियन नामक अखबार के सर्वे को सबके सामने रखा की जहाँ शुरू में वालमार्ट कीमतें कम करता है, एक बार जम जाने के बाद और दूसरी छोटी दुकानों को मैदान से बाहर करने के बाद कीमते 40 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। साथ ही सरकार के इस रोने–धोने का भी खुलासा किया के कैसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से भंडारण की कमी को नापा जा सकता हैं।

तीसरे सत्र में सबसे पहले तो बाड़मेर के जिले संयोजक श्री राजेंद्र सिंह भीमाड़ ने बताया के कैसे बड़मेर की सीमा पर भू–अधिग्रहण का षड़यंत्र चलाया गया और स्वदेशी जागरण मंच ने इसके खिलाफ बीड़ा उठाया और इसको रुकवाया। बीकानेर के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री धर्म प्रकाश ने इस विषय की सांगोपांग व्याख्या की, और इसके महत्त्व को दर्शाया।

श्री कश्मीरी लाल जी ने भू–अधिग्रहण की चुनौतियाँ के संदर्भ में कहा कि आज कई ग्रामों में ऐसे बदमाश पैदा हो गए है जो जबरदस्ती लोगो की जमीन पर कब्जा करके छोटा–मोटा मुआवजा देकर लोगों को चलता करते है, लोग डर के मारे कुछ बोलते नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है की राष्ट्रीय स्तर पर ये काम केंद्रीय सरकार कर रही है और प्रदेश स्तर पर प्रदेश सरकारे। लगभग हर रंग–रूप की सरकारे इस में शामिल है, बस अंतर केवल इतना है कि अपने प्रदेश में वे जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण करती है और दूसरी पार्टी के राज्य में इसका जमकर विरोध करती है। एक जगह नायक बनाती है, दूसरी जगह खलनायक और इससे मुद्दे को श्रेया दिया जाता है जिसने सिंगूर और नंदीगाम के कारण वहां की पुरानी जमी सरकार को उखड फेंका। वास्तव में ये विकास और भूमि स्वामित्व की लड़ाई नहीं, जैसा की प्रचारित किया जाता है, बल्कि ये तो बड़ी कंपनियो के स्वामित्व और आम आदमी के भूमि पर स्वामित्व की लड़ाई है।

एक महत्त्वपूर्ण सत्र में श्री मुरलीधर राव जी ने कहा कि जिस देश को दुनिया का नेतृत्व करना हो उसके पास सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्माण की तकनीक होनी चाहिए। उदहारण के लिए अभी मोबाइल की ही बात है, दूसरी बात विकेंद्रीकरण की नीतियां है जिसके सहारे समाज जिन्दा है और भूमड़लीकरण की प्रक्रिया का केन्द्रीयकरण करना, जिसके द्वारा भारत की आत्मा नष्ट करना चाहती ही। मंदिर हमारी इस समाज–आधारित व्यवस्था का अंग है। गौ माता हमारी विकेन्द्रित व्यस्था का प्राण है और गोचर भूमि जिस प्रकार से समाप्त की जा रही है उसके लिए भी जन–आन्दोलन चलने पड़ेंगे।

चीन की चुनौतियों का विषय श्री भगवती प्रकाश जी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक ने लिया। उन्होंने चीन सामनों द्वारा भारत के उद्योगों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। आज चीनी सामान हमारे शहरों के साथ–साथ गांवों में भी अपनी पैठ बना रहा है। जो एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि प्रत्येक गांवों में चीनी सामानों के विरोध एक अभियान चलाया जाए साथ ही लोगों को जागरूक बनाया जाए। ❑

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 27–7–2011

कुतर्कों के आधार पर सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों को खुदरा व्यापार में अनुमति की जल्दबाजी

संसदीय समिति के सिफारिशों को दरकिनार करते हुए, सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों को खुदरा क्षेत्र में अनुमति देने के फास्ट ट्रैक प्रयासों के संदर्भ में स्वदेशी जागरण मंच गंभीर चिंता व्यक्त करता है। 6 जुलाई 2010 को भारत सरकार ने एक चर्चा पत्र जारी कर खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति देने की अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। हालांकि उसी चर्चा पत्र में सरकार ने यह भी स्वीकार किया था कि संसदीय समिति ने इस हेतु अपना विरोध जताया था। इस चर्चा पत्र के जवाब में इस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न लोगों ने खुदरा व्यापार में विदेशी कंपनियों को अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। सरकार के इस फैसले से प्रभावित होने वाले वर्गों ने पहले से ही इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा हुआ है।

एक क्षेत्र जो 3.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और 1.5 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है, जो जीडीपी को 14 प्रतिशत भाग अर्जित करता है और जिसके बाजार का आकार 20 लाख करोड़ से भी अधिक है, सरकार द्वारा गैरजिम्मेदाराना तरीके से वालमार्ट और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। ऐसा लगता है कि यूपीए के नेतृत्व वाली भारत सरकार आजकल केवल वालमार्ट, बड़ी कंपनियों और अमरीकी सरकार की बातें ही मान रही है। हाल ही में वित्तमंत्री के सलाहकार कौशिक वसु ने अंतर–मंत्रालय समूह के प्रमुख के नाते यह तर्क दिया था कि खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति देने से देश में महंगाई को रोका जा सकेगा। कुछ दिन पहले सचिवों की एक समिति ने भी खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत विदेशी पूंजी को अनुमति देने का प्रस्ताव करते हुए इसी तर्क का सहारा लिया है।

यदि इन सिफारिशों को ध्यानपूर्वक देखा जाए तो पता लगता है कि यह आदेश कहां से आ रहा है। वास्तव में वालमार्ट एवं अन्य बड़ी खुदरा कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष एवं अमरीकी सरकार द्वारा भाड़े पर लिए गए सलाहकारों की रिपोर्टों से इन तर्कों को उठाया गया है। अंतर–मंत्रालय समूह की सिफारिशों और अमरीकी सरकार के सुझावों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता।

महंगाई रोकने का कुतर्क

एक ओर तो सरकार महंगाई रोकने में असफल सिद्ध हो रही है, तो दूसरी ओर इसी बात को खुदरा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को लाने के लिए तर्क के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि खुदरा क्षेत्र में वालमार्ट के आने से महंगाई कम हो जाएगी। बल्कि सच्चाई तो यह है कि भारत का खुदरा व्यापार जो 20 लाख करोड़ रुपए का है, आज मध्यम वर्ग के बढ़ती कमाई के कारण फल–फूल रहा है, यह अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। भारत में उद्यमशीलता के संरक्षण और बढ़ावा देने के बजाए सरकार अंतर्राष्ट्रीय समझौते करते हुए उसे बेचने की तैयारी कर रही है। आज का विकेंद्रीत खुदरा बाजार उपभोक्ताओं और उत्पादकों के लिए अत्यंत शुभकारी है। अगर बड़ी खुदरा कंपनियों को आने दिया जाएगा, तो वे न केवल उपभोक्ताओं बल्कि छोड़े उत्पादकों एवं किसानों पर अपनी शर्तें लादेगी। शोध से यह सिद्ध हो चुका है कि भारत से छोटे दुकानदार अत्यधिक कम लागत पर अपना व्यापार चलाने में सक्षम है। यह तर्क कि किसान को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा, कहीं सिद्ध नहीं हुआ है। शेयर बाजार की तर्ज पर वस्तुओं का एम.सी.एक्स. बाजार शुरू करने में भी यही तर्क दिया गया था कि इससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, जो एकदम गलत सिद्ध हुआ है।

हमें ध्यान रखना होगा कि खुदरा व्यापार के वर्तमान मॉडल को छेड़े जाने से देश में रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर भारी दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। आज कृषि में 60 प्रतिशत जनसंख्या संलग्न है। कृषि और अधिक लोगों को खपाने में सक्षम नहीं है। विनिर्माण क्षेत्र 21 प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है और उसमें वृद्धि की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से अतिरिक्त क्षमता का निर्माण नहीं हो रहा। ऐसे में खुदरा क्षेत्र ही एक मात्र क्षेत्र है जहां सबसे अधिक रोजगार है। यह क्षेत्र भी बैंकों द्वारा ऋण न दिए जाने के कारण और बड़ी भारतीय कंपनियों द्वारा खुदरा में आने से पहले से ही दबाव में है।

भण्डारण एवं कोल्ड स्टोरेज ढांचे का गलत तर्क

दुभार्ग्यपूर्ण है कि सरकार द्वारा भण्डारण और कोल्डस्टोरेज की सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपनी कमी को भी विदेशी कपंनियों को लाने के लिए तर्क के रूप में उपयोग कर रही है। सरकार स्वयं अथवा निजी क्षेत्र को भण्डारण एवं कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित कर सकती थी। सरकार द्वारा जारी चर्चा पत्र में यह कहा गया था कि देश में भण्डारण एवं कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 7687 करोड़ रुपए के लिए छोटे व्यापारियों के लिए मौत का वारंट दिया जाए, यह कहां तक ठीक है, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है।

सरकार का यह तर्क कि वर्तमान खुदरा व्यापारियों का नयी पद्धति में पुनर्वास हो सकेगा, हास्यास्पद है। छोटे व्यापारियों को नए मॉल्स में किसी भी प्रकार से सम्मानपूर्वक रोजगार नहीं मिल सकता। सरकार यदि मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार को खोलने की अनुमति देती है तो वह उसकी छोटे व्यापारियों, रेहड़ी–पटरी खोमचा लगाने वाले करोड़ों गरीबों के प्रति संवेदनहीनता का परिचायक होगा। ❑

प्रेस वक्तव्य

स्व.जा.मं. के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरूण ओझा द्वारा नई दिल्ली में दिनांक 6 अगस्त 2011 को पत्रकार वार्ता में जारी प्रेस वक्तव्य (खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश पर इक्रियर की रिपोर्ट का पर्दाफाश)

खुदरा व्यापार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति देने के संबंध में सचिव समूह समिति ने अपनी अनुशंसा के साथ केबिनेट में पारित करवाने के लिए भेजा है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं।

इस अनुमति के लिए केन्द्र सरकार ने 16 जुलाई 2011 को चर्चा पत्र आम जनता के लिए जारी किया गया था। इसमें 31 जुलाई 2011 तक अपनी आपत्तियां दर्ज करवाने का समय दिया गया था। देश के दुकानदारों को इसका पता भी नहीं चला। 12 पृष्ठ के इस चर्चा पत्र में 5 स्थानों पर केवल ईक्रियर नाम की शोध संस्था तथा 2 स्थानों पर प्राईस वाटर हाऊस कूपर नाम की संस्था की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। इन संस्थाओं की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुदरा व्यापार में प्रवेश देने की अनुमति की पैरवी की गई है। सरकार ने भारी राशि खर्च करके इक्रियर से वर्ष 2005 व 2008 में 2 बारे सर्वे करवाया है। यह एक संयोग है कि इस एजेंसी को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पैरोकार श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया की धर्मपत्नी श्रीमति ईशर आहलूवालिया चलाती है तथा दूसरी एजेंसी प्राईस वाटर हाऊस कूपर का नाम सत्यम घोटाले में जोर शोर से उछला था।

इक्रियर की मई 2008 की रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 7 को देखें तो उन्होंने देश भर में कुल 2825 दुकानदारों व उनके पड़ोसियों का सर्वे किया है। ये दुकानदार व उनके पड़ोसी कौन है व उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में देश नहीं जानता। 26 करोड़ लोगों की रोजी–रोटी से संबंधित निर्णय लेने का यह कौन सा तरीका है। दिनांक 8 जून 2009 को संसद की स्थायी समिति ने लोकसभा के पटल पर प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भी इसका कड़ा विरोध किया है।

इस संबंध में दुकानदारों को विषय से अवगत करवाने तथा उनकी राय जानने के लिए स्वदेशी जागरण मंच के उत्तर क्षेत्र के सह संयोजक श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' के नेतृत्व में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर व चंडीगढ़ में मंच के कार्यकर्ताओं ने दिनांक 1 जून से 30 जून 2011 तक एक अभियान चलाया। इस अभियान में 121 स्थानों पर कुल 37711 दुकानदारों से संपर्क किया गया तथा सभी दुकानदारों ने एकमत से सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर किए। इन स्थानों व हरताक्षरों का विवरण निम्नलिखित हैं–

प्रांत	कुल स्थान	कुल हस्ताक्षर
दिल्ली	16	14470
पंजाब	43	11511
चंडीगढ़	5	835
हिमाचल प्रदेश	27	3750
जम्मू	4	250
हरियाणा	26	6895
कुल	121	37711

मंच इक्रियर के इस सर्वे को चुनौती देता है। मंच के क्षेत्रीय संयोजक श्री कृष्ण शर्मा ने कहा कि संपर्क किए गए दुकानदारों के ज्ञापन को हम प्रधानमंत्री को सौंप रहे हैं तथा इन 37711 दुकानदारों की राय व उनका विवरण शीघ्र की हम अपनी वेबसाईट पर डाल रहे हैं। मंच सरकार से यह मांग करती है कि वह भी इक्रियर के द्वारा सर्वे किए गए दुकानदारों एवं उनकी राय से भी देश की जनता को अवगत करवाएं। ❑